Ranchi ● Friday, 26 September 2025 ● Year : 03 ● Issue : 251 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज
Published from Ranchi

राजधानी में दुर्गा पूजा का भक्तिमय माहौल परवान चढ़ने लगा है। जिला स्कूल मैदान में बन रहा पूजा पंडाल न सिर्फ अपने भव्य स्वरूप के लिए, बल्कि सुरक्षा की अनोखी पहल के कारण भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। गुरुवार को पूजा पंडाल आम लोगों के लिए खोल दिया गया। पट खुलते ही मां के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रामलला पूजा समिति की ओर से लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से पंडाल का निर्माण कराया गया है। यह पंडाल गुजरात के भुज स्थित स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप बनाया गया है।

मां का खुला पट

शारदीय नवरात्र : पांचवां दिन

मां स्कंदमाता का ध्यान

या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

BRIEF NEWS

आईएएस विनय चौबे ने हाईकोर्ट से मांगी बेल

RANCHI : हजारीबाग जिला का डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को विनय चौबे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। फिलहाल यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। विनय चौबे ने जिस मामले में हाईकोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। हजारीबाग एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने 16 सितंबर को इस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इंकार कर दिया था।

पुलिस महानिदेशक ने दिया नई जिंदगी के अवसर देने का आश्वासन

चाईबासा में 10 माओवादियों ने डीजीपी के सामने किया सरेंडर

PHOTON NEWS CHAIBASA : गुरुवार को चाईबासा में भाकपा (माओवादी) संगठन के 10 सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सभी ने राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता के सामने हथियार डाल दिए। यह आत्मसमर्पण झारखंड सरकार की उग्रवादी आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के तहत हुआ। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड की आत्मसमर्पण नीति देश की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वालों को नई जिंदगी के अवसर देने का आश्वासन दिया। साथ ही चेतावनी दी कि जो हथियार नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आत्मसमर्पण करने वालों में एक एरिया कमेटी सदस्य और नौ दस्ता सदस्य शामिल हैं। इनमें रांदो बोईपाई उर्फ कांति बोईपाई (एरिया कमेटी सदस्य) और गार्टी कोड़ा, जॉन उर्फ जोहन पुरती, निरसो सीदू उर्फ आशा, घोनोर देवगम, गोमेया कोड़ा उर्फ टारजन, कैरा कोड़ा, कैरी कायम उर्फ गुलांची, सावित्री गोप उर्फ मुतुरी उर्फ फुटबॉल और प्रदीप सिंह मुंडा (सभी दस्ता सदस्य) शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों का आपराधिक इतिहास भी है और इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।

आत्मसमर्पण करने वालों में में एक एरिया कमेटी और 9 दस्ता सदस्य, इनमें चार महिलाएं

- सभी के खिलाफ दर्ज हैं कई आपराधिक मामले
- सरकार की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में शामिल हो रहे नक्सली
- साल 2022 से 175 नक्सलियों को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में
- आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं नए कैंप

तीन वर्षों में 26 नक्सलियों ने टेके घुटने

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इसे झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगातार नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि विगत तीन वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम जिले से 26 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आज के आत्मसमर्पण से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है और चाईबासा और कोल्हान क्षेत्र में नक्सली और उग्रवादी गतिविधियों पर और अंकुश लगेगा। झारखंड पुलिस ने शेष नक्सलियों से भी अपील की है कि वे हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनें।

चल रहा प्रभावी अभियान

बताते चलें कि पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) के 'ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो' का संचालन केंद्रीय समिति सदस्य मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी उर्फ अनल और अन्य के नेतृत्व में किया जा रहा है। इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान दल लगातार अभियान चला रहे हैं। 2022 से अब तक पश्चिमी सिंहभूम में 9631 अभियान चलाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 175 नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि 10 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं।

राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएं चिकित्सक : हेमंत सोरेन

PHOTON NEWS RANCHI : गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में 160 चयनित चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें जेपीएससी द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापक, दंत चिकित्सक, एनएचएम के तहत संविदा आधारित चिकित्सा पदाधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि जेपीएससी के तहत 54 सहायक प्राध्यापक, 13 दंत चिकित्सक, एनएचएम के तहत 55 विशेषज्ञ चिकित्सक और 38 चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र देने ने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि धरती पर भगवान के रूप में आपकी नियुक्ति हो रही है। आपसे इस राज्य की गरीब, कमजोर और असहाय जनता को काफी आशा और उम्मीदें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी सेवा भावना से यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत और बेहतर करेंगे। अपनी सेवा से राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों से कहा कि आपने अपने कैरियर के रूप में स्वास्थ्य के क्षेत्र को चुना है।

- मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त 160 सहायक प्राध्यापकों, दंत चिकित्सकों और चिकित्सा पदाधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र
- नियुक्तियों की श्रृंखला में नित्य जुड़ रही हैं नई कड़ियां, आगे भी जारी रहेगा अभियान
- गरीब और असहाय जनता के प्रति यथार्थ में दिखनी चाहिए संवेदनाएं
- बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टरों को किया जाएगा सम्मानित

सीमित संसाधनों में कर सकते हैं बहुत कुछ

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास संसाधन सीमित है। लेकिन, इन सीमित संसाधनों के बीच भी करने के लिए काफी कुछ है। बस इसके लिए जुनून होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों को जितना इलाज की जरूरत है, उतना ही आपकी संवेदना और सेवा की भी। आप अपने व्यवहार और प्रभाव से मरीजों को काफी हद तक बेहतर माहौल दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नई चुनौतियां आ रही हैं। इसके लिए चिकित्सा के क्षेत्र बेहतर करने के लिए निरंतर अनुसंधान भी हो रहे हैं। इस दिशा में चिकित्सकों की काफी अहम भूमिका है। सरकार ने भी एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिसमें आप सभी का सहयोग लेकर स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करना है, ताकि लोगों को बेहतर इलाज के लिए संसाधन और सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नई-नई बीमारियां सामने आ रही हैं। लोग अलग-अलग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी समस्याएं मनुष्य द्वारा ही पैदा की जा रही है।

इंटरनेशनल ट्रेड शो का पीएम ने किया उद्घाटन, बोले-

डिफेंस कॉरिडोर से रक्षा क्षेत्र में भारत बन रहा आत्मनिर्भर

AGENCY GREATER NOIDA : गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ग्रेटर नोएडा में स्थित एक्सपो मार्ट में पांच दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। मौके पर पीएम ने हमारी सेनाएं स्वदेशी हथियार की लगातार मांग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर रक्षा से संबंधित कई उपकरण बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस के सहयोग से उत्तर प्रदेश में स्वचालित राइफल का निर्माण जल्द ही शुरू हो रहा है।

उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि आपसे मेरी कुछ अपेक्षाएं भी है। भारत में बनने वाला उत्पाद बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। मोदी ने कहा कि देशवासियों के मन में यह बात आई है की स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है।

जस्टिस आनंद सेन की अदालत में परीक्षा में हो रही देर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई

जेटेट होने तक नहीं होगी शिक्षकों की बहाली

PHOTON NEWS RANCHI : गुरुवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 2026 तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) आयोजित की जाए। अदालत ने साफ कहा कि जेटेट परीक्षा होने और उसके परिणाम आने तक राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू न करें। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में जेटेट में हो रही देर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने शिक्षा सचिव को हाजिर होने को कहा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव हाजिर हुए। सुनवाई के क्रम में अदालत ने शिक्षक पात्रता परीक्षा बीते 9 साल से नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि जो नियम है, उसका पालन जरूरी है।

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2026 तक परीक्षा कराने को कहा

401 उम्मीदवारों ने दायर की है याचिका

शिक्षक पात्रता परीक्षा मामले में हरिकेश महतो और अन्य 401 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज व अधिवक्ता कुशाल कुमार ने बहस की। अदालत ने सरकार से कहा गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अहम होती है। इसे लिए बिना नियुक्तियां नहीं हो सकतीं।

9 साल से प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार, 2016 के बाद झारखंड में नहीं हुई है शिक्षक पात्रता परीक्षा

कोर्ट ने पूछा- अब तक क्यों नहीं शुरू हुआ एग्जाम

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर 2016 के बाद जेटेट का आयोजन क्यों नहीं किया गया। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने जेटेट नियमावली में कहा है कि जिन्होंने 2016 में जेटेट पास की है, उनकी वैधता आजीवन रहेगी। उन्होंने अदालत को बताया कि वर्ष 2016 के बाद से अब तक लगभग नौ साल हो गए, लेकिन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया।

चिंताजनक एसएसआरसी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, भारत पर भी गहरा असर

सामाजिक विभाजन में बड़ी भूमिका निभा रहा सोशल मीडिया

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : समय के साथ समाज में बदलाव स्वाभाविक होता है। लेकिन, जब यह बदलाव कृत्रिम प्रभाव से आक्रांत होने लगता है, तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। आज के हाईटेक दौर में कुछ ऐसी ही तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। हाल में हुए रिसर्च से यह जानकारी सामने आ रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ता पोलराइजेशन (ध्रुवीकरण) अब लोकतांत्रिक संवाद के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। अमेरिका स्थित सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल (एसएसआरसी) की ताजा अंतरराष्ट्रीय स्टडी ने चेतावनी दी है कि एल्गोरिद्म की संरचना इस तरह काम कर रही है कि उपयोगकर्ता लगातार उन्हीं विचारों से जुड़ी सामग्री देखते हैं, जिससे समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है। सांस्कृतिक-राजनीतिक विभाजन और गहरे हो रहे हैं। एसएसआरसी के इस रिसर्च में अमेरिका, यूरोप, भारत, ब्राजील और दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़े डाटा का विश्लेषण किया गया। रिसेट की रिपोर्ट के अनुसार, चुनावी वर्षों और बड़े राजनीतिक आंदोलनों के दौरान ईको चैंबर का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है।

ध्रुवीकरण की बढ़ती स्थिति ने लोकतांत्रिक संवाद के सामने खड़ी की चुनौती

परस्पर बातचीत की शैली में बढ़ती कटुता से सहिष्णुता व सद्भाव में आ रही गिरावट

- रिसर्च में अमेरिका, यूरोप, भारत और ब्राजील से जुड़े डाटा का किया गया है विश्लेषण
- चुनावी वर्षों और राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दिखता है सबसे ज्यादा प्रभाव

18 से 30 आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित, क्योंकि यह उनका प्रमुख स्रोत

- अपने विरोधियों से संवाद के बजाय ब्लॉक या अनफॉलो करने की बढ़ रही प्रवृत्ति
- फेक न्यूज और नफरत फैलाने वाले कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए काम करता है सिस्टम

धार्मिक बहसों में आक्रामकता अधिक

नए रिसर्च में वैश्विक स्तर पर जो प्रमुख निष्कर्ष निकल कर आए हैं, उनमें राजनीतिक ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा है। लोग अपने विरोधियों से बातचीत करने के बजाय उन्हें ब्लॉक या अनफॉलो करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह अगर सांस्कृतिक पक्ष को देखा जाए तो धार्मिक और जातीय बहसें अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई हैं। 18 से 30 आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि उसकी खबरों का प्रमुख स्रोत सोशल मीडिया है।

लेह में जारी रहा कर्फ्यू स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण

LEH : लेह शहर में गुरुवार को भी कर्फ्यू जारी रहा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया गया, जिससे शहर में स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए थे। इस झड़प में अनियंत्रित भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी थी, स्थानीय भाजपा कार्यालय को जला दिया था और हिल काउंसिल के कार्यालय को आंशिक रूप से तहस-नहस कर दिया था। कांग्रेस नेता और पार्षद फुंटसोग स्टैनजिन त्सेपाग के खिलाफ भूख हड़ताल स्थल पर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया। गृह मंत्रालय ने हिंसा भड़काने के लिए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित भूख हड़ताल करने वालों को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा कार्यालय, लेह हिल काउंसिल कार्यालय और सीआरपीएफ जिप्सी को एक अनियंत्रित भीड़ ने आग लगा दी और पथराव में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे।

BRIEF NEWS

नशे में धुत युवक ने जूस बेचने वाले पर चलाई गोली

RAMGARH : रामगढ़ शहर के अनुमंडल कार्यालय के पास गुरुवार को दिनदहाड़े नशे में धुत्त एक युवक ने जूस बेचने वाले व्यक्ति पर गोली चला दी। जूस बेच रहे व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी की गोली उसे छूकर निकल गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही वहां अफरा तफरी मच गई। पेट्रोलिंग के दौरान पैंथर जवानों ने नशे में धुत्त उस युवक को पकड़ा और थाने ले आए। उस युवक की पहचान बरकाकाना ओपी क्षेत्र के घुटुवा निवासी धीरज कुमार उर्फ मोदी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और एक खोखा बरामद किया है। रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि गोली चलाने वाला युवक नशे में था। जूस बेचने वाले से उसने जूस मांगा । इस दौरान हुई देरी की वजह से उसने अपना आपा खो दिया। इस घटना की सच्चाई तब सामने आएगी जब इलाज करा कर जूस बेचने वाला व्यक्ति थाने आएगा। पुलिस धीरज कुमार उर्फ मोदी का कुंडली खंगाल रही है।

नवजात की मौत पर अस्पताल में हंगामा

DHANBAD : बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के मेमको मोड़ स्थित श्रीराम अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा कर स्थानीय लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। इसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों को शांत करा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में मरीज के परिजन गुलाम अंसारी ने बताया कि बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के ही सुसनीलेवा के रहने वाले सुलेमान अंसारी की पत्नी रेशमा खातून को प्रसव के लिए गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के बाद एक बच्ची का जन्म हुआ। प्रसूति भी स्वस्थ थी। तभी अचानक अस्पताल के कर्मचारियों ने आकर उन्हें मृत बच्ची सौंप दिया। परिजनों ने जब बच्ची की मौत का कारण जानने के लिए बच्ची को गौर से देखा तो मृत बच्ची के सिर पर चोट के गहरे निशान थे। इसके बाद मृत बच्ची के परिजन शव को लेकर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के वक्त बच्ची को डॉक्टरों ने जमीन पर गिरा दिया, इससे नवजात बच्ची की मौत हो गई। वहीं, घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और मामले की जांच में जुट गई है।

एंबुलेंस से बरामद हुआ 43 किलो डोडा का चूरा

HAZARIBAG : चौपारण थाना की पुलिस ने गुरुवार को एंबुलेंस से 43.650 किलो डोडा का चूरा बरामद किया है। इसकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। बताया जाता है कि गुप्त सूचना पर चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदाहा चेकनाका में पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बिहार की ओर से आ रही मारुति वैन एंबुलेंस को रोकने का प्रयास किया गया, तो पुलिस को देखते ही चालक एंबुलेंस छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन वह फरार हो गया। एंबुलेंस की तलाशी लेने पर अगले हिस्से और पिछली केबिन में थैलों में भरा डोडा चूरा छिपाकर रखा गया था।

एक साथ पांच लोगों की हत्या करने वाले चुन्नू मांझी को फांसी की सजा

2019 के मामले में चांडिल अनुमंडल कोर्ट ने सुनाया फैसला

PHOTON NEWS SERAIKELA : सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिन्द्र नाथ सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को पांच लोगों की हत्या के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस घटना में दोषी करार दिए गए अभियुक्त चुन्नू मांझी उर्फ पुतस मांझी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फांसी की सजा के साथ उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना और धारा-427 में दो साल कैद की सजा भी दी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

23 फरवरी 2019 को तड़के करीब चार बजे चुन्नू मांझी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचा और अपने रिश्तेदार रवि मांझी, उसकी पत्नी कल्पना उर्फ पावों और उसके तीन बच्चों - जितेंद्र, सुरेश और पुरेश की निर्मम हत्या कर दी थी। वारदात के बाद उसने वादी और उसकी मां पर हमला किया तथा घर और बाइक को आग के हवाले कर दिया था। इसी मामले में यह सजा सुनाई गई है। यह मामला सिद्धू सोरेन (भाई) के बयान पर दर्ज हुआ था। पुलिस ने चुन्नु मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और एफएसएल की रिपोर्ट सहित आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक हर्षवर्धन ने इस जघन्य हत्याकांड को दुर्लभ प्रकृति का बताते हुए फांसी की सजा की मांग की। मामले में कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। कपाली ओपी ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को सबूत के तौर पर पेश किया।

नागाडीह मॉब लिंचिंग मामले में 5 दोषी करार सजा के बिंदु पर 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई

JAMSHEDPUR : बागबेड़ा के नागाडीह गांव में 18 मई 2017 को मॉब लिंचिंग के दौरान हुई 4 लोगों की हत्या के मामले में गुरुवार को घटना के पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामले में सजा के बिंदु पर 8 अक्टूबर को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेश सहाय सुनवाई करेंगे। कोर्ट की ओर से मामले मे पूर्व मुखिया राजाराम हांसदा, रेंगो पूर्ति, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार और तारा मंडल को दोषी करार दिया गया है। इसके अलावा बाकी के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। राजाराम हांसदा की बात करें तो वे घटना के तीसरे दिन से ही जेल में हैं। गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने जमानत लेना भी मुनासिब नहीं समझा था। राजाराम को घटना का मुख्य आरोपी बनाया गया था। आरोप लगाया गया था कि गांव वालों की तरफ से सबसे पहले वे ही टांगी लेकर हमला करने के लिए दौड़े थे। नागाडीह हत्याकांड में 27 नामजद और 300 अज्ञात के खिलाफ बागबेड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। घटना के समय बागबेड़ा के थाना प्रभारी आमिश हुसैन थे और विधि-व्यवस्था डीएसपी बिमल कुमार थे। नागाडीह की घटना में जुगसलाई नया बाजार के दो भाई गौतम वर्मा, विकास वर्मा, रामसखी देवी (76) और बागबेड़ा गाराबासा का दोस्त गंगेश गुप्ता शामिल है। घटना के संबंध में उत्तम वर्मा के बयान पर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। मामला सुर्खियों में आने के बाद थानेदार इंसपेक्टर आमिश हुसैन को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद नया थाना प्रभारी के रूप में राकेश रंजन को बागबेड़ा थाने में पदस्थापित किया गया था।

सीसीएल के गार्डों से भिड़े कोयला चुनने वाले ग्रामीण

अस्पताल में इलाजरत सुरक्षाकर्मी

● फोटोन न्यूज

RAMGARH : रामगढ़ जिले के रजरप्पा क्षेत्र में सीसीएल के सुरक्षाकर्मी और कोयला चुनने वाले लोगों के बीच एक बार फिर भिड़ंत हुई है। इस पथराव में दो सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए हैं। गुरुवार को कोयला चुनने गई कुछ महिलाएं और युवकों को सीसीएल के सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा। उनसे कोयला छीना और इस दौरान कुछ लोगों के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद कोयला चुनने वाले ग्रामीण भी उग्र हो गए। उन लोगों ने भी पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी आशीष झा के सिर पर चोट लगी। इसके अलावा अन्य कर्मचारी को भी चोटे आई हैं। घायल सुरक्षा अधिकारी आशीष झा एवं उनके साथी का इलाज सीसीएल हॉस्पिटल रजरप्पा में कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही रजरप्पा पुलिस मौके पर पहुंची। उन लोगों ने सीसीएल के सुरक्षा अधिकारियों को सुरक्षित कर ग्रामीणों को खदेड़ा। सीसीएल के सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा आवेदन देने के बाद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी।

राहुल दुबे गैंग के तीन अपराधी गिरफ्तार दो पिस्टल व सात गोलियां बरामद

कोठार स्थित एक होटल से अरेस्ट किए गए सभी अपराधी

AGENCY RAMGARH : जिले के भुरकुंडा क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले राहुल दुबे गैंग के तीन शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से दो पिस्टल, सात गोली और तीन मोबाइल बरामद हुआ है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान एसपी अजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में रांची रोड, मरार, मिश्रा टोला निवासी तुषार मिश्रा उर्फ सौम्या मिश्रा उर्फ मिश्रा, धनबाद जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा जमुआ निवासी मंगलेश कुमार उर्फ मंगलेश और हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत महुगाई कला गांव निवासी मुकेश कुमार उर्फ मुकु शामिल है।

पत्रकारों को मामले की जानकारी देते एसपी अजय कुमार

होटल में योजना बनाते धरे गए अपराधी

एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गैंग के सक्रिय सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए रामगढ़ के कोठार स्थित एक होटल में रुके हुए हैं। तत्काल पुलिस ने वहां छापेमारी की तो तुषार, मंगलेश और मुकेश की गिरफ्तारी हो गई। पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ की गई दोनों घटनाओं में इस्तेमाल किए गए पिस्टल बरामद हुआ। इसके अलावा सात जिंदा गोली, एक पिस्तौल का मैगजीन भी पुलिस को मिला।

सेंट्रल साउंड व आरए माइनिंग साइट पर चलाई थी गोली

एसपी ने बताया कि राहुल दुबे गैंग के इन शातिर अपराधियों ने 18 अगस्त और 29 अगस्त को दो अलग-अलग स्थानों पर गोली चलाई थी। भुरकुंडा स्थित आरए मीनिंग के साइट पर रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की। इसके बाद सेंट्रल सौंदा भुरकुंडा सीसीएल रेलवे साइडिंग स्थित पप्पू जैन के साइट पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना के बाद पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई।

कुजू के महुआ टुंगरी में भी गोली चलाने वाले थे अपराधी

एसपी अजय कुमार ने बताया कि राहुल दुबे गैंग के सभी अपराधी कुजू ओपी क्षेत्र के महुआ टुंगरी में भी फायरिंग करने की योजना बना रहे थे। वे लोग व्यापारियों, ठेकेदारों और काम करने वाले लोगों को फोन कर धमकाते थे और रंगदारी वसूलते थे। उन लोगों को राहुल दुबे से सीधे निर्देश मिलता था। यहां तक कि किस व्यक्ति को कब फोन करना है, यह सारे निर्देश राहुल दुबे ही उन्हें देता था। एसपी ने बताया कि छापेमारी दल में शामिल सभी पदाधिकारी और जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्हें अवार्ड भी मिलेगा। छापेमारी दल में पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी, पतरातू इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार, पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता, भुरकुंडा ओपी प्रभारी निर्भय कुमार गुप्ता, भदानी नगर ओपी प्रभारी अख्तर अली आदि शामिल थे।

झारखंड में 41 केवीए से ज्यादा के डीजी सेट में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र अनिवार्य

छह माह की दी गई मोहलत, इसके बाद सीधे होगी जुर्माने व जब्ती की सख्त कार्रवाई

PHOTON NEWS DHANBAD : झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (जीएसपीसीबी) ने राज्य में चल रहे डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट के लिए अहम नियम बनाया है। इसके तहत 41 केवीए से 1000 केवीए तक की क्षमता वाले डीजी सेट में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (इमिशन कंट्रोल डिवाइस) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्देश नए और पुराने, सभी तरह के जेनरेटर सेट के लिए है। पहले से लगे जेनरेटर सेट को भी नियम का पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का नियम जारी किया गया है। इससे पहले 01 फरवरी 2022 में भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रेट्रो-फिट इमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) के लिए दिशा-निर्देश जारी किया था। इसे 24 जुलाई 2023 को संशोधित भी किया गया था। इसका उद्देश्य डीजल जेनरेटर से निकलने वाले धूल व धुएं सहित अन्य हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। बोर्ड ने सभी संस्थानों-प्रतिष्ठानों को छह माह की मोहलत दी है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि छह माह के बाद बिना प्रदूषण नियंत्रण यंत्र वाले जेनरेटर को जब्त किया जाएगा और इसके मालिक पर जुमार्ना भी लगाया जाएगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार, धनबाद में 130 से अधिक जेनरेटर सेट नए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्षेत्रीय पदाधिकारी के अनुसार, सभी जेनरेटर मालिकों की सूची तैयार की जा रही है, उन्हें पहले नोटिस भेजकर आगाह किया जाएगा।

20 वर्ष पुराने जेनरेटर पर प्रतिबंध

- प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अनुसार, जुलाई 2004 से पहले निर्मित या स्टेज-1 व स्टेज-2 मानकों का पालन न करने वाले सभी जेनरेटर सेट किसी भी परिस्थिति में चलने नहीं दिए जाएंगे। इन्हें तत्काल नष्ट करना होगा। 20 वर्ष पुराने जेनरेटर की खरी-बिक्री पर भी प्रतिबंध है।
- 800 किलोवाट (1000 केवीए) तक के जेनरेटर सेट में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनुमोदित उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण ही लगाना है।
- 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले डीजी सेट में कम से कम 70 प्रतिशत उत्सर्जन (कार्बन मोनोआक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एवं हाइड्रोकार्बन) की कमी सुनिश्चित करनी होगी।
- उपकरणों का परीक्षण आईएसओ मानक के अनुसार केवल सीपीसीबी मान्यता प्राप्त एजेंसियों से ही कराना है।
- गैस आधारित जेनरेटर को बढ़ावा देने के लिए आंशिक गैस उपयोग या नए गैस आधारित जेनरेटर लगाने पर जोर दिया गया है।

> सभी संस्थानों, उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों को आदेश जारी होने की तारीख से छह माह के अंदर इस पर अनुपालन करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम-1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
>
> – राजीव लोचन बख्शी
> सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

हजारीबाग में हुई डकैती के सभी अपराधी गिरफ्तार

HAZARIBAG : हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 13 सितंबर को हुई 80 लाख की डकैती के सभी नौ अपराधी गिरफ्तार का लिए गए। इनके पास से पुलिस ने लूटे गए सभी गहने भी बरामद कर लिए। यहां बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बभनी में अनंदिता मल्लिक के घर में रात को घुसकर जान मारने की धमकी देते हुए अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। टीम कांड के अनुसंधान में जुटी थी। इसी बीच एसपी को गुप्त सूचना मिली कि हत्यारी जंगल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद हैं। इस सूचना पर डकैती कांड के मुख्य अभियुक्त रणवीर कुमार सिंह उर्फ छोटु उर्फ जोकर, सन्नी कुमार गुप्ता, राहुल कुमार यादव और विपुल कुमार सिंह उर्फ सुशील कुमार को हत्यारी जंगल से गिरफ्तार किया गया। इनसे लूटे गए जेवरात व एक पिस्टल बरामद किया गया। रणवीर कुमार सिंह की निशानदेही पर कांड के अन्य अभियुक्त राजेश कुमार यादव, सुरेंद्र उरांव, विपिन कुमार सिंह, रवि राय और दिनेश कुमार यादव उर्फ सन्नी को गिरफ्तार किया गया तथा कांड में लूटे गए शेष जेवरात एवं घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई।

प्रधानाचार्य ने छात्राओं से की अभद्र बात, हुआ खूब हंगामा

AGENCY DHANBAD : गोविंदपुर थाना क्षेत्र बरवा पूर्व स्थित पीएम श्रीमहेंद्र +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा पर विद्यालय की ही छात्राओं ने अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को विद्यालय के मुख्य गेट पर हंगामा करते हुए प्रधानाचार्य को निलंबित करने की मांग की है।

स्कूल परिसर में हंगामा करतीं छात्राएं

विद्यालय गेट पर हंगामा कर रही छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में परीक्षा चल रही है। वहीं विद्यालय में परीक्षा के दौरान बैठने के लिए बेंच वगैरह नही होने पर छात्राओं ने विद्यालय के प्रधानाचार्य से परीक्षा के समय बैठने के लिए बेंच टेबल की मांग की, ताकि वह परीक्षा दे सके। लेकिन विद्यालय के प्रधानाचार्य ने छात्राओं को अश्लील तरीके से उन्हें अपनी गोदी में बैठाने की बात कही। अपने ही विद्यालय के प्रधानचार्य की ओर से छात्राओं पर अश्लील टिप्पणी करने से नाराज विद्यालय की छात्राएं विद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठ कर जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग से विद्यालय के प्रधानचार्य के निलंबन की मांग करने लगे। इसके बाद मौके पर छात्राओं के परिजन भी पहुंच गए और छात्राओं के साथ हंगामा करने लगे। माहौल बिगड़ता देख गोविंदपुर थाना सूचना पाकर मौके पर पहुंची और छात्राओं एवं उनके परिजनों को शांत कराया। साथ ही मामले की जांच के बाद प्रधानाचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस संबंध में धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने मामले की जानकारी नही होने की बात कही।

धर्म-अध्यात्म झारखंड-बिहार की सीमा पर हंटरगंज प्रखंड स्थित कोल्हुआ पर्वत पर विराजमान है माता का मंदिर

कुल और कोख की रक्षा करती हैं मां कौलेश्वरी, देश-विदेश से आते हैं श्रद्धालु

PHOTON NEWS CHATRA : झारखंड और बिहार राज्य के सीमा पर स्थित हंटरगंज प्रखंड का कोल्हुआ पर्वत जिसे कौलेश्वरी भी कहा जाता है, यह तीन धर्मों का संगम स्थली है। नवरात्र में कोल्हुआ पर्वत देश-विदेश के श्रद्धालु पहुंचते हैं। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर नवरात्र में यहां लाखों की भीड़ उमड़ती है। यह पर्वत रामायण और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है।

1755 फीट की ऊंचाई पर कोल्हुआ पहाड़ी की चोटी पर माता कौलेश्वरी का एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर महाभारत कालीन है। राजा विराट ने पहाड़ी की चोटी पर माता कौलेश्वरी की प्रतिमा स्थापित कराई थी। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां निवास किया था।

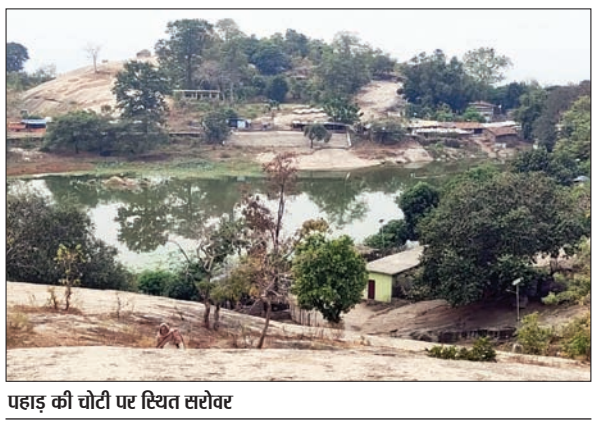
पहाड़ की चोटी पर स्थित सरोवर

मंदिर में विराजमान माता की मूर्ति

पांडवों ने भी की थी मां कौलेश्वरी की आराधना

द्रौपदी के संग पांडवों ने माता कौलेश्वरी की आराधना की थी। माता के इस स्वरूप का दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन है। पुराणों में वर्णित राजा सूरथ ने भी यहां तपस्या की थी। पहाड़ी की चोटी पर भी आकाश लोचन और भीम गुफा कई रहस्यों और मान्यताओं से भरा पड़ी है। जैन धर्म के लिए भी यह स्थल पूजनीय है।

महाभारत काल में यह स्थल राजा विराट की राजधानी थी। यह स्थल झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड से 15 किलोमीटर दूर कोल्हुआ पहाड़ पर है। यह झारखंड का चर्चित पर्यटन स्थल है। इसके विकास को लेकर राज्य सरकार ने रोडमैप तैयार किया है। यहां रोप वे सहित कई योजनाएं प्रस्तावित हैं।

बच्चों की नजर सीधी करने के लिए पहुंचते हैं भक्त

शारदीय नवरात्र में मां के दर्शन व पूजन के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर यहां साल भर लोगों का आना-जाना लगा रहता है। खासकर बच्चों की नजर सीधी करने के लिए भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि मां कौलेश्वरी कुल और कोख की रक्षा करती हैं। जिन बच्चों की नजर टेढ़ी हो जाती है वे मां के दर्शन मात्र से ही ठीक हो जाते हैं। आसपास के लोगों में मान्यता है कि माता कुलेश्वरी कुल और संतान की रक्षा करती हैं। यहां एक ही पत्थर को तराश कर मां कौलेश्वरी की एक पांच फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। चतुर्भुजी शक्ति स्वरूपा हैं। आसपास के लोगों की माता के प्रति अटूट आस्था है। रामायण काल में वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने भी यहां निवास किया था। यह मंदिर मोक्षदायिनी फल्गु जिसे निरंजना भी कहा जाता है आसपास से ही गुजरती है। पहाड़ी की चोटी में एक प्राचीन सरोवर भी है जिसमें साल भर पानी रहता है। कौलेश्वरी मंदिर झारखंड का एक ऐसा धार्मिक तीर्थ स्थल है जिसकी ख्याति आसपास ही नहीं देश-विदेश में भी है। कई देशों के लोग यहां विभिन्न अनुष्ठान के लिए पहुंचते हैं। संभवतः झारखंड में यह एक मात्र ऐसा स्थल है। जहां धार्मिक गतिविधियों के लिए सर्वाधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। यह जगह तीन धर्मों की संगम स्थली के रूप में विख्यात है।

रामगढ़ में बच्चे के साथ कुएं में गिरा हाथी, निकाला गया

कुएं में बच्चे के साथ दिख रहा हाथी ● फोटोन न्यूज

RAMGARH : रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में गुरुवार को एक हाथी अपने बच्चे के साथ अर्धनिर्मित कुएं में गिर गया। हेसापोड़ा पंचायत अंतर्गत परसाडीह के जंगल में सुबह हुई घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुट गई। विभाग ने पोकलेन मशीन मंगाकर कुएं के एक भाग को ध्वस्त कराया गया, ताकि हाथी व उसके बच्चे को सुरक्षित निकाला जा सके। दूसरी ओर, कुएं में दो हाथी के डूबने की खबर पाकर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। गोला थाना की पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मुस्तैद हो गई। काफी देर के बाद दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। गोला प्रखंड में बच्चे के साथ हाथी के कुएं में गिरने की घटना दूसरी बार हुई है। 10 वर्ष पहले भी एक हाथी व बच्चा कुएं में डूब गए थे। उन्हें भी वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से लगभग पांच घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। इसके बाद दोनों को जंगल की ओर भेज दिया गया। यहां बता दें कि गोला प्रखंड के वन क्षेत्र में फिलहाल एक दर्जन हाथी मंडरा रहे हैं। इनमें से तीन हथिनी ने बच्चे को जन्म दिया है।

पुलिस और सुरक्षा बलों के आक्रामक रुख ने नक्सलियों की तोड़ दी रीढ़

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में जिला पुलिस और सुरक्षा बलों की आक्रामक एक्टिविटी के कारण नक्सली दहशत में हैं। वे या तो एनकाउंटर में मारे जा रहे या सरेंडर कर रहे हैं। धीरे-धीरे अन्य सहित इनामी नक्सलियों की संख्या कम हो रही है और इसका आर्थिक फायदा भी पुलिस को हो रहा है। इस साल 9 महीनों में झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को गहरे और गंभीर जख्म दिए हैं। आलम ऐसा है कि कभी 200 की संख्या में इनामी राशि वाले नक्सलियों की संख्या घटकर आज 43 रह गई है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान की दृष्टि से देखें तो सबसे खास रहा इस साल का अप्रैल का महीना, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक करोड़ के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया। इसके बाद से अब तक पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ होती रही। इसमें कई और इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया। अब झारखंड पुलिस केंद्रीय बलों की मदद से इन इनामी राशियों से अपना खजाना भर रही है। आलम यह है कि साल 2025 के पहले 9 महीने में ही झारखंड पुलिस को करोड़ों के राजस्व का फायदा हुआ है। इनामी नक्सलियों और अपराधियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद यह सब संभव हो पाया है। इस बीच ऑपरेशन के खौफ से कई नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और उनकी जान भी बच गई और उन पर रखी इनाम की राशि भी उन्हें मिल गई।

झारखंड में अब 200 से घटकर 43 रह गई है इनामी नक्सलियों की तादाद, अप्रैल तक 61 थे ऐसे नक्सली

इस साल के पिछले 9 महीनों में नक्सलियों को मिले हैं गहरे जख्म, कई ने हथियार डालकर बचाई अपनी जान

- एनकाउंटर में मारे गए कुछ नक्सलियों पर थी 3 करोड़ 11 लाख रुपये की इनाम राशि
- 15 सितंबर को हुई मुठभेड़ में मारा गया एक करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन
- 25 और 10 लाख के इनामी रघुनाथ हेंब्रम और बिरसेन गंझू भी कर दिए गए ढेर

विवेक और सहदेव जैसे खूंखार नक्सलियों से मुक्त हुआ प्रदेश

साल 2025 के अप्रैल महीने तक तो 61 इनामी थे, लेकिन अब मात्र 43 ही बचे हैं। झारखंड पुलिस के द्वारा तबाड़तोड़ कार्रवाई की वजह से इनामी नक्सलियों की संख्या में भारी कमी आई है। इनामी नक्सलियों को एनकाउंटर में मारकर पुलिस अपना खजाना भर रही है। इस साल के मात्र दो एनकाउंटर में ही पुलिस ने दो करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। अप्रैल 2025 में एक करोड़ के इनामी विवेक और फिर सितंबर माह में एक करोड़ के इनामी सहदेव सोरेन को एनकाउंटर में मार गिराया। इससे दो करोड़ की इनाम की राशि झारखंड और केंद्रीय बलों के जवानों के नाम हो गई। झारखंड पुलिस द्वारा साल 2025 में 29 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर में मारे गए इनामी नक्सलियों कि कुल इनाम की राशि 3 करोड़ 11 लाख रुपये होती है।

सुनियोजित तरीके से अभियान को दिया गया अंजाम

हजारीबाग जिले के गोहरर थाना क्षेत्र में 15 सितंबर को हुई मुठभेड़ में एक करोड़ इनामी नक्सली सहदेव सोरेन मारा गया। इसके साथ 25 लाख इनामी रघुनाथ हेंब्रम और 10 लाख इनामी बिरसेन गंझू मारे गए। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोइलकेरा में 08 सितंबर को हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली अमित हांसदा उर्फ अपटन ढेर हो गया। 05 अगस्त को गुमला में पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के कमांडर 15 लाख का इनामी उग्रवादी मार्टिन केरकेट्टा सहित दो को मार गिराये गये। बोकारो में 16 जुलाई को सुरक्षा बलों ने 25 लाख के इनामी कुंवर मांझी सहित दो नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया।

सरेंडर करें, नहीं तो मारे जाएंगे : डीजीपी

झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि झारखंड में जोरदार अभियान जारी है, सभी फरार नक्सलियों को टारगेट किया जा रहा है। नक्सलियों को यह संदेश भी दिया गया है कि वह आत्मसमर्पण करें नहीं तो पुलिस के साथ अगर मुठभेड़ होगी तो उनका मारा जाना तय है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि हमारा ज्यादा फोकस अब सारंडा में छुपे तीन एक एक करोड़ के इनामी नक्सलियों पर है। हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वे पकड़े जाते हैं तो पूरे नक्सली संगठन का मनोबल ही टूट जाएगा। झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। एक तो जंगलों और बीहड़ों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों के खिलाफ साई आप्स भी चलाया जा रहा है। साई आप्स के तहत इनामी नक्सलियों के पोस्टर नक्सल प्रभावित इलाकों में लगाये गए हैं। इन पोस्टर्स में नक्सलियों की तस्वीर, उनके ऊपर घोषित इनाम की राशि

और पुलिस अफसरों के मोबाइल नंबर दिया गया है। पोस्टर देखकर पहचान कर नक्सलियों की खबर पुलिस तक पहुंचाने वालों को नक्सलियो के ऊपर घोषित इनाम की राशि दी जाएगी। नक्सलियों का पता बताने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इसका जोरदार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है।

SHARE

सेंसेक्स	:	81,137.35
निफ्टी	:	24,885.05

SARAFA

सोना	:	10,650
चांदी	:	150.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

भैरव सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

RANCHI : गुरुवार को हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। भैरव सिंह की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई के बाद उसने अपनी याचिका वापस ले ली है। भैरव सिंह ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाते हुए जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट का रूख देखते हुए उसने अपनी याचिका वापस ले ली।

राजगंज थाना प्रभारी के खिलाफ याचिका दायर

RANCHI : जामताड़ा के रहने वाले रामचंद्र महतो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर धनबाद जिला के राजगंज थाना प्रभारी अलीशा कुमारी को पद से हटाने और आरक्षण का गलत लाभ लेने के लिए बर्खास्त करने की मांग की है। इससे पहले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अलीशा कुमारी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश जारी किया था।

जांच की गुणवत्ता सुधारने पर अधिकारियों ने दिया जोर

राज्य स्तरीय कार्यशाला में झारखंड को मलेरिया मुक्त बनाने की रणनीति

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड को 2030 तक मलेरिया से पूरी तरह मुक्त करने के उद्देश्य से रांची में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड और टीसीआई फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित की गई। जिसमें मलेरिया से बचाव, रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के नेतृत्व में वर्ष 2030 तक राज्य को मलेरिया मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की रणनीति का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब जमीनी स्तर पर कार्य हो और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

इस साल राज्य में मलेरिया के अब तक 22 हजार मामले आए सामने

8 राज्यों के प्रतिभागी हुए शामिल

डॉ. कल्पना बरुआ एनसीवीबीडीसी भारत सरकार ने झारखंड में मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित कर उनके कार्यों के प्रति उत्साहवर्धन किया। वर्चुअल माध्यम से जुड़ीं डॉ. रिंकू शर्मा, संयुक्त निदेशक एनसीवीबीडीसी ने मलेरिया जांच की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला में 8 राज्यों बिहार, झारखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आए 31 अधिकारी शामिल हुए। इन अधिकारियों को मलेरिया उन्मूलन की रणनीतियों पर प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला में डॉ. मुनिस चंद्र, डॉ. रमेश धीमन, सुश्री नमिता मेहता, डॉ. महेश कौशिक और डॉ. दिनकर समेत कई विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।

पिछले साल की तुलना में 50% कम मामले

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. बीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 2025 में झारखंड में लगभग 22 हजार मलेरिया के मामले सामने आए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत कम हैं। उन्होंने कहा कि मच्छरों की रोकथाम के लिए नियमित कीटनाशक छिड़काव, बुखार के मरीजों की समय पर जांच और उपचार जैसे उपायों के कारण यह सफलता मिली है। वहीं डब्ल्यूएचओ के वेक्टर बॉर्न डिजीज आफिसर डॉ. अभिषेक पॉल ने कहा कि मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट कर और समय पर उपचार देकर मलेरिया के मामलों में भारी कमी लाई जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि समय पर निदान और जागरूकता से असमय मौतों को रोका जा सकता है।

700 गाड़ियों की पार्किंग के साथ खाने और मनोरंजन का होगा इंतजाम

राजधानी के सैनिक बाजार में बनेगा ट्विन टावर, मॉल में मिलेंगी सुविधाएं

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची की हृदयस्थली में स्थित सैनिक बाजार अब नए रूप में नजर आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकसित शहरीकरण के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए नगर विकास विभाग ने यहां वृहद मॉल निर्माण की कवायद शुरू कर दी है। इस परियोजना का डिजाइन प्रेजेंटेशन गुरुवार को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार की अध्यक्षता में दिया गया। परामर्शी संस्था मास एंड वायड द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक डिजाइन में कुल 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण प्रस्तावित है।

परियोजना का मुख्य आकर्षण 11 मंजिला ट्विन टावर होगा। जिसमें ऑफिस स्पेस और शो रूम की सुविधा होगी। कुल 9 लाख वर्ग फीट में बनने वाले इस मॉल सह ऑफिस काम्प्लेक्स का बिल्ट-अप एरिया 6 लाख वर्ग फीट होगा, जिसमें 700 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था दो बेसमेंट में की जाएगी। प्रेजेंटेशन के दौरान जुडको के पीडीटी विनय कुमार राय और पीडीएफ सह एडमिन अमित कुमार चक्रवर्ती उपस्थित थे। इस प्रोजेक्ट को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक बंद घर में अचानक लग गई आग

जलकर राख हुआ गरीब परिवार का हर सपना, जमीन के कागजात भी नहीं बचे

PHOTON NEWS RANCHI : रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक घर में गुरुवार को अचानक आग लग गई। इस आगलगी में एक गरीब परिवार का हर सपना जलकर राख हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घर मालिक का सब कुछ स्वाहा हो गया। आग लगने की वजह से आसपास के मकान वाले भी दहशत में आ गए। आग बुझाने के लिए लोग अपनी छतों पर से ही पानी फेंकना शुरू कर दिया। कुछ ने तो अपने टंकी खोल दी। लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। जब तक फायर

ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जिस घर में आग लगी उसमें पति-पत्नी उषा देवी और उज्वल साहू अपने बच्चों के साथ किरायेदार के तौर पर रहा करते थे। सुबह के समय उषा देवी अपने काम पर चली गई थी। जबकि उनके पति उज्वल भी बच्चों को स्कूल भेज कर अपर बाजार स्थित दुकान पर काम करने के लिए चले गए थे। उषा देवी ने बताया कि लगभग ढाई लाख का सामान तो जल ही गया, साथ ही साथ घर में रखे जमीन के कागजात भी जल गए।

नई पहल — ग्रामीण समाज को जागरूक बनाने के लिए कारगर स्कीम

पंचायत ज्ञान केंद्रों के माध्यम से दी जा रही योजनाओं की जानकारी

PHOTON NEWS RANCHI : हेमंत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और जनहित की योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत इस साल राज्य की 999 पंचायतों में पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल ग्रामीण समाज को सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिलेगी, बल्कि शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक ठोस आधार तैयार होगा। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित करने की योजना 2022-23 में प्रारंभ हुई थी। पहले चरण में 500 पंचायतों में केंद्र स्थापित किए गए। इसके बाद 2023-24 में 1000 पंचायतों में, 2024-25 में 998 पंचायतों में और 2025-26 में 999 पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अंतिम चरण 2026-27 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत ज्ञान केंद्र होगा। यह योजना धीरे-धीरे पूरे राज्य को डिजिटल और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है।

गांव के लोगों को इन केंद्रों के माध्यम से शिक्षित बनाने की भी है योजना

सरकार ने इस साल योजना के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट किया तय

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश की 999 पंचायतों में स्थापित किए जा रहे ये केंद्र
- आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक ठोस आधार तैयार करना है स्कीम का लक्ष्य

योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी

पंचायत ज्ञान केंद्रों का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण समाज में पठन-पाठन और स्व-शिक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह केंद्र न केवल शिक्षा और ई-लर्निंग का माध्यम बनेंगे, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र होंगे। यहां से सरकारी योजनाओं की सही और समय पर जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे ग्रामीण जनता को लाभ उठाने में आसानी होगी। आज की पीढ़ी डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ रही है। लेकिन, गांवों में इंटरनेट, किताबें और संसाधनों की कमी के कारण यह सुविधा सीमित है।

केंद्र के संचालन की व्यवस्था

केंद्रों के संचालन के लिए पंचायत स्तर पर पुस्तकालय प्रबंधन एवं सलाह समिति गठित की जाएगी। इसमें पंचायत मुखिया, पंचायत सेवक, सेवानिवृत्त शिक्षक, महिला संगठन की प्रतिनिधि, युवा और स्थानीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक शामिल होंगे। एक प्रशिक्षित लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी की जाएगी, जो पुस्तकालय और डिजिटल संसाधनों का संचालन संभालेगा। राज्य स्तर पर भी पुस्तक दान अभियान चलाया जाएगा, ताकि केंद्रों में पुस्तकों की कमी न हो और लगातार उनका विस्तार होता रहे। इस प्रकार, स्थानीय समुदाय को भी इस योजना से सीधे जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

एलेविटा मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2025 के फाइनल में पहुंची तृप्ति लकड़ा

RANCHI : झारखंड की बेटी तृप्ति कुमारी लकड़ा ने एक बार फिर अपने जज्बे और मेहनत से राज्य का नाम रोशन किया है। उनका चयन एलेविटा मिसिज इंडिया वर्ल्ड 2025 के अंतिम चरण के लिए हुआ है, जिसे मिसेज वर्ल्ड जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता का आधिकारिक भारतीय चयन द्वार माना जाता है। अपनी उपलब्धि पर रांची के पिस्?का स्थित अपने आवास पर गुरुवार को मीडिया से बात करते तृप्ति ने कहा कि यह मंच केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और उद्देश्य का है। वे कहती हैं हर महिला यह महसूस करे कि वह असीमित है। पशु-पक्षियों, विशेषकर कुत्तों के प्रति उनके गहरे लगाव ने उन्हें डर्टी पॉज नामक ब्रांड की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। यह ब्रांड न सिर्फ पालतू जानवरों के लिए आभूषण और एक्सेसरीज बनाता है, बल्कि सड़क पर रहने वाले कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर भी तैयार करता है, ताकि वे रात के समय सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षित रह सकें।

NEWS BOX

एसएसपी ने देर रात शहर का किया निरीक्षण

RANCHI : झारखंड की राजधानी रांची के एसएसपी राकेश रंजन अचानक शहर की विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतर आए। उनके इस औचक निरीक्षण की खबर किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मी को पहले से नहीं थी। बुधवार की देर रात लगभग एक बजे एसएसपी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने बिरसा चौक, मेन रोड, हरमू बायपास रोड और अरगोड़ा चौक सहित शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने उनसे वाहनों की चेकिंग और पुलिस बल की तैनाती के बारे में जानकारी ली। साथ ही एसएसपी ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए। एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो या उसे किसी भी प्रभावशाली समूह का संरक्षण क्यों न मिला हो, पुलिस को बिना किसी दबाव के उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को बिना किसी दबाव के कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि शहर में सुरक्षा और शांति बनी रहे। उन्होंने बताया कि विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को निरीक्षण किया गया है। आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री से आईजी ने की मुलाकात

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आईजी, बोकारो सुनील भास्कर ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी।

लाइब्रेरी भवन का जल्द पूरा होगा जीर्णोद्धार

RANCHI : आईएएस वाइव्स एसोसिएशन के प्रयासों से बेड़ो प्रखंड में लाइब्रेरी खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गुरुवार को जिला अभियंता गुप्तेश्वर राम ने टीम के साथ पुराना प्रखंड भवन का निरीक्षण किया, जहां जीर्णोद्धार कार्य अंतिम चरण में है। पुराने प्रखंड भवन में ही पुस्तकालय, वाचनालय एवं शौचालय का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जिला अभियंता गुप्तेश्वर राम ने बताया कि इस पुस्तकालय से आम लोगों को बेहतर अध्ययन सुविधा मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बेड़ो प्रखंड की नई पहचान बनेगी। छोटे बच्चों के बैठकर पढ़ने के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। लाइब्रेरी भवन के समीप ही प्रज्ञा केंद्र है, जहां ग्रामीण अपनी आवश्यक सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। निरीक्षण के दौरान कनीय अभियंता संजीत कुमार और संवेदक टाइगरस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर केदार गोप भी मौजूद थे।

बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग

RANCHI : राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले में न केवल सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी जांच को कमजोर करने का काम किया। बाबूलाल ने कहा कि निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, पूर्व आईएएस अमित प्रकाश, जेएसबीसीएल के पदाधिकारी सुधीर कुमार दास समेत छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी और नकली होलोग्राम सप्लाई करने वाले विधू गुप्ता जैसे बड़े नाम इस घोटाले में शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसीबी ने 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसके कारण सभी मुख्य आरोपी आसानी से जमानत पर छूट गए। उन्होंने कहा कि ये किसी साजिश से कम नहीं है। बाबूलाल ने हाल ही में एसीबी में हुए तबादलों को भी संदिग्ध बताया और सवाल उठाया कि आखिर किसके इशारे पर अधिकारियों को पहले नियुक्त किया गया और फिर अचानक हटा दिया गया। साथ ही मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। साथ ही, एसीबी के उन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने चार्जशीट दाखिल करने में देरी की।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैंपिंग शुरू

RANCHI : विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रांची जिला प्रशासन और पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पर्यटन जागरूकता अभियान का आयोजन 21 से 27 सितंबर तक किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को रूरल इमर्शन एंड कल्चरल सेलिब्रेशन प्रोग्राम के तहत कैंपिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और उप-विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने समाहरणालय परिसर से इच्छुक पर्यटकों की बस को हरी झंडी दिखाकर रातू प्रखंड के पाली गांव के लिए रवाना किया। इस मौके पर जिला नजारत उप-समाहर्ता डॉ. सुदेश कुमार, जिला खेल पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि यह अभियान न केवल झारखंड की खूबसूरत ग्रामीण और प्राकृतिक धरोहर से पर्यटकों को परिचित कराने का प्रयास है, बल्कि इसे विश्व पटल पर राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने का अवसर भी है।

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की हुई बैठक

RANCHI : समाहरणालय सभागार में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह-अध्यक्ष मंजूनाथ भजन्त्री ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जेनमें प्रमुख रूप से लंबित योजनाएं जल्द पूरी करना रहा। बैठक में अब तक स्वीकृत और लंबित योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने साफ निर्देश दिया कि सभी एजेंसियां समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण काम करें और वित्तीय नियमों का पालन करें। डीएमएफटी की नई गाइडलाइन के अनुसार, रांची जिला में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पंचायतों और गांवों की सूची की समीक्षा की गई। सर्वसम्मति से तय हुआ कि कुछ नए गांव-पंचायत भी इस सूची में जोड़े जाएंगे।

समाचार सार

एमबीएनएस में घूमर व गरबा की रही धूम

JAMSHEDPUR : पारडीह काली मंदिर के पास आसनबनी स्थित एमबीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में गुरुवार को नवरात्र की खुशी में घूमर व गरबा गाला-2025 का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व छात्रों ने भी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विवेक सिंह (अध्यक्ष) व अनुपा सिंह (निदेशक) ने छात्र-छात्राओं को नवरात्र की बधाई दी। अंत में सभी ने फूड स्टॉल से डोसा, चाट, पापड़ी, दही-वड़ा, चाउमिन आदि का आनंद उठाया।

स्वच्छता अभियान में डीसी ने भी लगाई झाड़ू

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम की जिला जल एवं स्वच्छता समिति के तत्वावधान में गुरुवार को स्वच्छता ही सेवा-स्वच्छोत्सव-2025 अभियान चलाया गया, जिसमें डीसी चंदन कुमार ने भी झाड़ू पकड़ी। कार्यक्रम की शुरूआत पोस्ट ऑफिस चौक से हुई, जहां सभी ने मोहल्ले व शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। स्वच्छता श्रमदान सदर बाजार क्षेत्र में भी चला। एक दिन-एक घंटा-एक साथ नामक स्वच्छता श्रमदान इस कार्यक्रम में उपविकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, अपर उपायुक्त प्रवीण केरकेट्टा, चाईबासा-सदर के अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग समेत अन्य पदाधिकारी, नगर परिषद, सीआरपीएफ, सामाजिक व व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

सोना देवी विवि में कंप्यूटर लैब का हुआ उद्घाटन

GHATSILA : सोना देवी विश्वविद्यालय में गुरुवार को कुलाधिपति प्रभाकर सिंह ने कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. डॉ. गुलाब सिंह आजाद व परीक्षा नियंत्रक मिथिलेश सिंह भी उपस्थित थे। इस लैब में छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीक सीख सकेंगे।

कराइकेला में अज्ञात व्यक्ति की मौत

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराइकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कंसारा गांव में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई, जो कई दिनों से बीमार था और गांव में अलग-अलग घरों में खाना मांगकर गुजारा कर रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल, चक्रधरपुर भेजा गया है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए शव को पहचान के लिए विधिक अवधि तक शीतगृह में रखा जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शव की पहचान का प्रयास जारी है।

स्टेशन परिसर से हटाई गईं अतिक्रमित दुकानें

CHAKRADHARPUR : दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर गुरुवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें ठेल-दुकान हटाए गए। सड़क जाम करने के आरोप में तीन ऑटो भी जब्त किए गए। इसकी निगरानी चक्रधरपुर रेलवे मंडल के सहायक सुरक्षा आयुक्त एसी सिन्हा कर रहे थे। सिन्हा ने बताया कि स्टेशन के बाहर अवैध रूप से लगाए गए ठेलों के कारण वहां गंदगी फैल रही थी, जिस पर डीआरएम ने आरपीएफ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि स्टेशन के बाहर का क्षेत्र साफ-सुथरा और व्यवस्थित बना रहे।

मानगो नगर निगम का टेंडर डीसी ने किया रद

JAMSHEDPUR : मानगो नगर निगम द्वारा विभिन्न इलाकों में करोड़ों रुपये की लागत से पेवर्स ब्लॉक लगाने का टेंडर जारी किया गया था, लेकिन निविदा प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इसमें गड़बड़ी का मामला उजागर हो गया। इसके बाद डीसी कर्ण सत्यार्थी ने इस टेंडर को रद कर दिया है। भाजपा के पूर्व नेता विकास सिंह ने प्रमाण के साथ उपायुक्त को बताया था कि जेएनएसी क्षेत्र में एम-40 ग्रेड का पेवर्स ब्लॉक 798 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से लग रहा है, जबकि मानगो नगर निगम ने एम-35 ग्रेड की कम ताकत वाली ईंट 890.56 रुपये प्रति वर्गमीटर पर लगाने का टेंडर निकाला था। इससे साफ था कि इस निर्माण कार्य में हेराफेरी होने जा रही थी। एक ही शहर में टेंडर प्रक्रिया में कम गुणवत्ता के रेट वाली ईंट का दाम अच्छी गुणवत्ता वाली ईंट के दाम से अधिक रखा गया था। विकास सिंह ने आरोप लगाया कि सांसद और विधायक मानगो क्षेत्र में नहीं रहते, इसलिए नगर निगम ने जानबूझकर कम गुणवत्ता और महंगे पेवर्स ब्लॉक लगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इससे करोड़ों के राजस्व का भी नुकसान होता।

सरायकेला में कंटेनर से टकराई कार, चालक की मौत, 5 घायल

टाटा-रांची एनएच पर तेज रफ्तार कार ने आगे चल रहे वाहन को मार दी टक्कर

PHOTON NEWS SERAIKELA : सरायकेला-खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा-रांची राष्ट्रीय उच्च पथ पर गुरुवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। दारुदा गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने अपने आगे चल रहे कंटेनर में टक्कर मार दी। इससे कार चालक वाहन के अंदर ही बुरी तरह फंस गया।

पुलिस ने गैस कटर से कार को काटकर चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे में कार में सवार अन्य पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में दो महिलाएं शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर में धंसी कार करीब 300 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और स्थानीय लोगों के प्रयास से सड़क को कुछ घंटों बाद खाली कराया गया। पुलिस ने बताया कि मृत चालक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने कंटेनर और क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

कार में फंसा चालक ● फोटोन न्यूज

नदी की तेज धार में बह गया ट्रैक्टर चालक, झाड़ियों में मिला शव

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत कोवाली थाना क्षेत्र में बहने वाली नागा नदी की तेज धार में एक ट्रैक्टर चालक बह गया। गंगाडीह पंचायत अंतर्गत केंदमुड़ी गांव के 60 वर्षीय राजबल्लभ गोप की मौत नदी में डूबने से हो गई। मंगलवार को वह राशन लेने के बाद मछली पकड़ने नदी किनारे पहुंचा था, जहां बारिश के कारण नागा नदी में अचानक तेज बहाव आ गया। इस बहाव में राजबल्लभ संभल नहीं सका और वह तेज धारा में बह गया। गुरुवार को उसका शव घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला। मृतक के भाई प्राण बल्लभ गोप ने बताया कि मंगलवार को राजबल्लभ ट्रैक्टर चलाने के बाद जनवितरण प्रणाली की दुकान से राशन लेकर लौट रहा था। इसी दौरान वह नदी किनारे मछली पकड़ने लगा। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और तेज धार की चपेट में आने से वह डूब गया। परिजनों ने बुधवार को कोवाली थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने खोजबीन शुरू की और गुरुवार को नदी किनारे झाड़ियों में शव मिला। परिजनों ने शव की पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

भालूबासा में 7 कारतूस के साथ एक गिरफ्तार भेजा गया जेल

JAMSHEDPUR : सीतारामडेरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके भालूबासा मुस्लिम बस्ती से शुभम कुमार दुबे उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार किया है। इस बीच उसकी तलाशी के क्रम में जेब से 7 कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस को आशंका है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक मे होगा। घटना के संबंध में सीतारामडेरा थाने में एएसआई राजीव कुमार मंडल के बयान पर अवैध रूप से कारतूस रखने का एक मामला दर्ज किया गया है। आरोपी शुभम भालूबासा के रोड नंबर 4 का रहने वाला है। पुलिस ने शुभम से पूछताछ करने के बाद गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार युवक-युवती की घटनास्थल पर हुई मौत

महादेवशाल स्थित सैप कैंप के पास हुई दुर्घटना, दोनों ने नहीं पहना था हेलमेट

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा-मनोहरपुर मार्ग पर गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार युवक-युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना महादेवशाल स्थित सैप कैंप के पास दोपहर करीब तीन बजे हुई। मृतकों में युवक की पहचान गोइलकेरा के खूंटपाई निवासी 18 वर्षीय पोंडेराम हाईबुरु के रूप में हुई है, जबकि युवती मनोहरपुर प्रखंड के सोनपोखरी की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही गोइलकेरा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए चक्रधरपुर भेज दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, युवक हीरो ग्लैमर बाइक पर सवार होकर युवती को लेकर डेरावां छोर से गोइलकेरा की ओर आ रहा था। युवती पीछे बैठी थी। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी और फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के सिर में गंभीर चोट लगी। हादसे के बाद आसपास के लोग जुट गए। राहगीरों की भीड़ लग गई। हादसे के कारण मार्ग में यातायात भी बाधित हुआ, जिसे बाद में पुलिस ने चालू कराया। पुलिस ने घटनास्थल पर एक मालवाहक वाहन को खड़ा पाया, जिसका नंबर सीजी04एनडब्ल्यू/6879 है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी मालवाहक वाहन को ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे दूसरे वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और भाग निकला। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।

घटनास्थल पर पड़े शव ● फोटोन न्यूज

केयू ने 5 लाख तक बढ़ाई प्रोविडेंट फंड लोन की सीमा, शिक्षकों को राहत

JAMSHEDPUR : कोल्हान विश्वविद्यालय में कुलपति डॉ. अंजिला गुप्ता की अध्यक्षता में हुई के सिंडिकेट की बैठक में भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) के तहत कॉलेजों के प्राचार्यों, शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए लोन की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी। इसके अतिरिक्त, जिन शिक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि रुका हुआ था, उन्हें भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही, डेढ़ साल पहले नियुक्त हुए शिक्षकों की सेवाओं को भी स्थायी (कन्फर्म) कर दिया गया है, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

काशीडीह पंडाल का खुला पट

काशीडीह स्थित ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब द्वारा बनाए गए दुर्गा पूजा के पंडाल का गुरुवार को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद बिद्युत बरण महतो भी उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत भाजपा नेता अभय सिंह ने किया।

कुड़मियों की मांग के विरोध में आदिवासी छात्रों ने किया प्रदर्शन

नारेबाजी करते आदिवासी छात्र संघ के नेता ● फोटोन न्यूज

GHATSILA : राजस्टेट मैदान से फूलडुंगरी चौक तक आदिवासी छात्र संघ (एसीएस), पूर्वी सिंहभूम के बैनर तले गुरुवार को बाइक रैली के साथ प्रदर्शन किया, जिसमें आदिवासी का दर्जा देने वाली कुड़मियों की मांग का विरोध किया गया। अध्यक्ष अजीत कुमार मुर्मू के नेतृत्व में निकली रैली में संघ के जिला प्रभारी सह जिला कोषाध्यक्ष सुपाई सिंह हांसदा, केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुनाथ हांसदा, सुदाम हेम्ब्रम, संजय मुर्मू, दान्दु मांडी, ब्रह्मकिशोर मुर्मू, बाबूजीत हेम्ब्रम, लखन मांडी, कुनाराम हांसदा, इंद्रो मुर्मू, ईश्वर चंद्र मुर्मू, सालखु मार्डी सहित काफी संख्या में छात्राएं भी शामिल थीं। अजीत मुर्मू ने बताया कि कुर्मी, कुड़मी या महतो लोग जिस जाति में हैं, उसी में रहें, आपसी भाईचारा में मतभेद पैदा ना करें, आजादी से पहले एसटी का हवाला देते हैं तो ओबीसी में रहकर अलग कॉलम की मांग करें। इससे उन्हें भी फायदा होगा और आदिवासियों का हक भी सुरक्षित रहेगा।

साकची के बोधि मंदिर मैदान में 14 नवंबर से लगेगा चौथा बाल मेला

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय द्वारा आयोजित चौथा बाल मेला इस बार 14 से 20 नवंबर तक साकची के बोधि मंदिर मैदान में होगा। यह निर्णय सरयू राय द्वारा आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में मेले का संयोजक सुधीर सिंह को बनाने की घोषणा हुई। बैठक के बारे में मंजू सिंह ने बताया कि 14 नवंबर को बाल मेले का उद्घाटन और 20 नवंबर को समापन होगा। बैठक में जदयू विधायक ने कहा कि इस मेले में जमशेदपुर के सभी स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो भी बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें गूगल फॉर्म भरना होगा। बहुत जल्द गूगल फॉर्म सभी स्कूलों को भेज दिया जाएगा। दुर्गा पूजा के बाद सभी स्कूलों को निमंत्रण भेजा जाएगा और निजी तौर पर उनसे संपर्क भी साधा जाएगा। मंजू सिंह ने बताया कि मेले में बच्चों के लिए लाभकारी स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा सातों दिन अलग-अलग आयु समूह के बच्चों के लिए खेलकूद, क्विज, योगा, चित्रांकन, निबंध, भाषण, गीत, नृत्य आदि प्रतियोगिता होगी।

दुर्गा पूजा के दौरान बैंकों व ज्वेलरी शॉप के लिए रहेगी विशेष सुरक्षा

लौहनगरी में सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी, एसएसपी ने जवानों को दिए सख्त निर्देश

PHOTON NEWS JSR : दुर्गा पूजा के मौके पर शहर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लौहनगरी की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया है। त्योहार को देखते हुए पुलिस की चप्पे-चप्पे पर चौकसी की गई है। कंट्रोल रूम के जरिए शहर की निगरानी चल रही है। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि त्योहार के दौरान खास तौर से बैंकों, ज्वेलरी शॉप और अपार्टमेंट की विशेष सुरक्षा की जाएगी। इन इलाकों में गश्त बढ़ाने को कहा गया है ताकि, पर्व के दौरान कोई बड़ी आपराधिक घटना नहीं हो। महिला सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। गुरुवार को साकची स्थित सीसीआर में एसएसपी पीयूष पांडे ने पुलिस अधिकारियों और जवानों की ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि इन दिनों बाजार और पंडालों में भीड़ सबसे ज्यादा रहती है, ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि कोई भी श्रद्धालु या आम नागरिक असुविधा का सामना न करे। एसएसपी ने जवानों को निर्देश दिया कि दिन में कम से कम दो बार पंडालों में जरूर जाएं। अगर कहीं कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु दिखे, तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दें। पंडालों के आसपास असामाजिक तत्वों पर भी विशेष नजर रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सभी जवान कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क में रहें। गश्ती के लिए उपलब्ध बाइक और हैंडसेट का उपयोग करें।

पुलिसकर्मियों को संबोधित करते एसएसपी पीयूष पांडेय ● फोटोन न्यूज

बाजार का हाल कुछ दुकानदार ग्राहकों को दे रहे कम कीमत पर सामान, अधिकतर कर रहे पुराना स्टॉक पड़ा होने की बात

जीएसटी की दरें कम होने पर भी बाजार में ऊहापोह की स्थिति

PHOTON NEWS JSR : केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरें घटा दी हैं। लेकिन, जमशेदपुर में कुछ दुकानों पर ही ग्राहकों को इसका लाभ मिल रहा है। अधिकतर दुकानों पर पुराने महंगे रेट पर ही सामान बेचे जा रहे हैं। इससे ग्राहकों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ग्राहकों ने दुकानदारों से जीएसटी की दरें कम होने का हवाला दिया तो जवाब मिला कि अभी उनके पास जो सामान है, वह जीएसटी रेट की पुरानी दरों का है। इसलिए, अभी महंगे पुराने रेट पर ही सामान बेचा जा रहा है। गुरुवार को जीएसटी की दरें कम होने के बाद बाजार का माहौल लेने निकले। मानगो में कई दुकानों पर दस्तक दी। मानगो रोड नंबर 15 में गुमटी में पनीर, बटर, दूध, दही आदि बेचने वाले दुकानदार रामकुमार से हमने पूछा कि 1 लीटर दूध कितने का है। उन्होंने तपाक से जवाब दिया 60 रुपये। जब उनसे जीएसटी की दरें कम होने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी पुरानी जीएसटी दरों पर ही समान बेचा जा रहा है। कम रेट पर समान मिलेगा तो कम रेट पर बेचा जाएगा। अभी डीलर की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कई दुकानों में पुराने रेट पर ही बिक रहे सामान

मानगो के जवाहर नगर में किराना की दुकान चलाने वाले मोहम्मद आजम ने 1 लीटर दूध का दाम 62 रुपये बताया। उन्होंने बाजार में चल रहे रेट से 2 रुपये अधिक बताया। इसका कारण पूछने पर मोहम्मद आजम का कहना था कि वह फ्रिज में दूध ठंडा करने के लिए 2 रुपये ले रहे हैं। जब उनसे कहा गया कि बाकी अन्य दुकानदार और शहर में 60 रुपये का ही 1 लीटर दूध मिलता है तो उनका जवाब था कि वहीं से ले लीजिए। डिमना रोड पर किराना दुकानदार रमेश कुमार बताते हैं कि अभी सस्ती जीएसटी दरों पर सामान नहीं आया है। अभी उनकी दुकान में पुराना समान है। इसीलिए वह पुराने रेट पर ही सारा सामान बेच रहे हैं। मानगो के मलिक स्टोर पर भी अभी पुराने रेट पर ही अधिकतर सामान बेच जा रहे हैं। यहां 200 ग्राम बटर का दाम 120 रुपये है। 1 किलो दूध 60 रुपये में बिक रहा है। 1 किलो दही का दाम 72 रुपये है, जबकि 70 ग्राम चीज का दाम 139 रुपये है।

साबुन व बटर भी हुआ सस्ता

5 पीस लक्स साबुन का बंडल पहले 110 रुपये में बेचा जा रहा था। अब यह 98 रुपये में दिया जा रहा है। पनीर का दाम भी घटा है। अमूल पनीर का 200 ग्राम का पैकेट सस्ता हुआ है। यह पैकेट पहले 95 रुपये में बेचा जाता था। सोमवार को इसे 88 रुपये में बेचा जा रहा है। पारले-जी बिस्कुट के दाम भी घटे हैं। पारले-जी बिस्कुट का 800 ग्राम का पैकेट पहले 100 रुपये में था। सोमवार को इसे 83 रुपये में बेचा गया। इसी तरह सर्फ एक्सेल बार डिटर्जेंट के 200 ग्राम का पैकेट भी सस्ता हुआ है। यह डिटर्जेंट 128 रुपये में 200 ग्राम दिया जा रहा था। सोमवार को इसका दाम कम करने के बाद इसे 108 रुपये में बेचा जा रहा है। पारले का न्यूट्री क्रंच डाइजेस्टिव का एक किलोग्राम का पैकेट पहले 320 रुपये में था। अब इसे 142 रुपये में दिया जा रहा है। अमूल गाय का 500 ग्राम घी का पैकेट पहले 330 रुपये में बेचा जाता था। अब इसकी कीमत 299 रुपये हो गई है। यहां अमूल बटर का 500 ग्राम का पैकेट पहले 305 रुपये में बिक रहा था। सोमवार को इसका दाम 281 रुपये हो गया है।

शॉपिंग मॉल ग्राहकों को दे रहे जीएसटी का फायदा

बड़े शॉपिंग मॉल में जीएसटी का फायदा मिल रहा है। मानगो में अपना मार्ट जीएसटी का फायदा दे रहा है। यहां कई चीजों के दाम कम हुए हैं। वहां बाकायदा पोस्टर लगाकर बताया जा रहा है कि जीएसटी के रेट कम होने से कितने सामान सस्ते हुए हैं। यहां कई समान सस्ते किए गए हैं। यहां 500 ग्राम बादाम पहले 559 रुपये का था। अब जीएसटी की दरें कम होने के बाद इसे 399 में बेचा जा रहा है। गोला स्पंज का दाम पहले 299 रुपये था, अब यह 13 रुपये सस्ता होकर 245 रुपये में बिक रहा है। हल्दीराम भुजिया का पैकेट भी सस्ता हुआ है। 1 किलोग्राम भुजिया का दाम पहले 290 रुपये लिया जा रहा था। अब ग्राहकों को 258 रुपये में भुजिया दी जा रही है। विम डिश वॉश बार का भी दाम घटा है। 500 ग्राम विम डिश बार पहले 60 में थी। अब इसे 46 रुपये में दिया जा रहा है। यहां ड्राई छोला भी सस्ता हुआ है। 500 ग्राम ड्राई छोला के पैकेट का दाम पहले 219 रुपये था। अब इसका दाम घटकर 157 रुपये हो गया है।

जमशेदपुर के चित्रकार अर्जुन दास ने बनाई दिशोम गुरु की पेंटिंग

पेंटिंग देखते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : सोनारी निवासी चित्रकार अर्जुन दास ने झामुमो के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पेंटिंग बनाई है। बुधवार की शाम रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने यह पेंटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेंट की। पेंटिंग देखते ही मुख्यमंत्री भावुक हो उठे और अर्जुन की प्रतिभा को सराहते हुए कहा कि झारखंड की मिट्टी में अपार प्रतिभा है। अर्जुन जैसे कलाकार हमारी संस्कृति और विरासत को संजोने का कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार हमेशा ऐसे युवाओं के साथ खड़ी है। अर्जुन दास ने कहा कि यह क्षण उनके जीवन का सबसे यादगार पल रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति को कला के माध्यम से सहेजना मेरे लिए गर्व की बात है। पेंटिंग तैयार करने के बाद अर्जुन दास ने झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई थी। कुणाल षाड़ंगी की पहल पर मुख्यमंत्री ने कलाकार को अपने आवास बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की धरती से निकली प्रतिभाएं आज राज्य की पहचान बन रही हैं।

शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है कुंजल क्रिया

भारत में योग का चलन आज से नहीं बल्कि सदियों से रहा है। योग महज एक शारीरिक व्यायाम नहीं है। बल्कि यह जीवन को सरल और बेहतर बनाने का एक बेजोड़ तरीका है। आज हम आपको योगा की एक ऐसी ही टेक्निक से रूबरू कराएंगे। जो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को तो बाहर निकालती ही है। साथ ही आपको कई दूसरे लाभ भी देती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुंजल क्रिया के बारे में। यह अन्य योगासन से बहुत भिन्न है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस क्रिया में आपको उल्टी करनी होती है। हां शायद यह आपको थोड़ी अजीब लग सकती है। लेकिन कुंजल क्रिया सही मायने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आइए जानते हैं इस क्रिया के बारे में।

क्या आपने कभी कुंजल क्रिया के बारे में कुछ सुना है। अगर नहीं तो यह क्रिया आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। आइए जानते हैं कुंजल क्रिया के बारे में और जानते हैं कैसे यह आपकी सेहत पर असर डालती है।

क्या है कुंजल क्रिया

कुंजल क्रिया आपके शरीर से अशुद्धियां बाहर निकालने की एक जबरदस्त टेक्निक है। कुंजल क्रिया के बारे में सबसे पहले हठयोग से संबंधी एक प्रदीपिका ग्रंथ में दिया गया था। इस ग्रंथ में ही इसे शरीर की सफाई करने की तकनीक के रूप में बताया गया है। कुंजल क्रिया न केवल आपके शरीर को साफ करती है बल्कि यह आपके मन को भी नियंत्रित करने में भी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में इसे लेकर एक शोध भी प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि उल्टी करने के बाद व्यक्ति को खालीपन महसूस होता है और इससे कई शारीरिक लाभ होते हैं। आइए जानते हैं कैसे की जाती है कुंजल क्रिया।

कैसे होती है कुंजल क्रिया

- इसके लिए आपको कम से कम 6 से 8 गिलास गुनगुने पानी की जरूरत होगी और हर एक लीटर पानी पर एक चम्मच सेंधा नमक या साधारण नमक भी चाहिए होगा।
- अब आपको एक लीटर पानी में एक चम्मच सेंधा नमक मिलाना होगा और कगासन की मुद्रा में बैठना होगा।
- इसके बाद आपको इसी मुद्रा में यह पानी जल्दी से जल्दी पीना होगा और उल्टी करने के लिए थोड़ा आगे झुक कर खड़ा होना होगा।
- जब आपको लगे की पेट खाली हो चुका है तो शवासन की मुद्रा में 30 मिनट के लिए लेट जाएं।
- इस क्रिया में आपको उल्टी तुरंत आ जाती है। ऐसे में अगर यह क्रिया करें तो विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें।

वजन और पाचन के लिए

जब भी आप कुंजल क्रिया करते हैं तो इससे आपके पेट की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और फैट कम हो जाता है। ऐसे में अगर आप फैट या वजन कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो य क्रिया आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। यह पाचन तंत्र को पूरी तरह स्वस्थ रखने काम काम करती है।

तनाव और चिंता से राहत

जब आप इस क्रिया को करते हैं तो इससे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है और आपके शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचने लगता है। इससे आपका हार्ट रेट कम हो जाता है और सांस लेना भी आसान हो जाता है। साथ ही यह ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुंजल क्रिया के जरिए तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। ध्यान रहे कि यह क्रिया किसी विशेषज्ञ की

या फिर आपकी आयु 16 साल से कम है तो इस आसन को बिल्कुल ना करें।

खांसी और सर्दी से राहत

जब आप कुंजल क्रिया करते हैं तो इससे आपके फेफड़ों की मांसपेशियां मजबूत होती है और इनकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही इसके जरिए आपके फेफड़े भी साफ हो जाते हैं और आपके लिए सांस लेना आसान हो जाता है। इस तरह यह सर्दी और खांसी के लक्षणों से राहत दिलाती है।

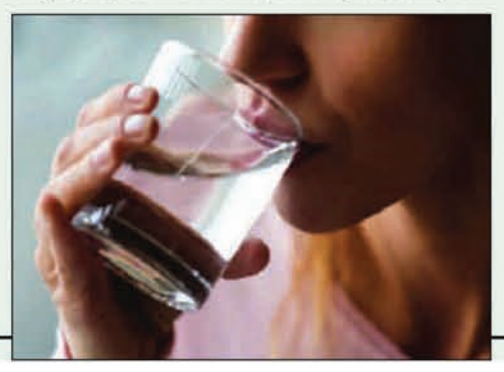

एलईडी और टीएफटी स्क्रीन से निकलने वाली सफेद रोशनी आंखों को तनाव में डालती है। आयुर्वेद के अनुसार, संपूर्ण शरीर की तरह आंख भी तत्वों से संबंधित है। आंख की मांसपेशियां पृथ्वी तत्व द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि ब्लड वेसल्स अग्नि द्वारा और आंखों का रंग हवा से नियंत्रित होता है।

ऐसे करें आंखों की देखभाल

मोबाइल और लैपटॉप के बढ़ते इस्तेमाल के कारण हमारी आंखों का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा हो रहा है। जिससे लोगों में सिरदर्द, जलन और आंखों में तनाव के मामले बढ़े हैं। खासकर, एलईडी और टीएफटी स्क्रीन से निकलने वाली सफेद रोशनी आंखों को तनाव में डालती है। आयुर्वेद के अनुसार, संपूर्ण शरीर की तरह आंख भी तत्वों से संबंधित है। आंख की मांसपेशियां पृथ्वी तत्व द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि ब्लड वेसल्स अग्नि द्वारा और आंखों का रंग हवा से नियंत्रित होता है। आंखें पित्त दोष का आसन हैं। चूंकि पित्त दोष उम्र के साथ असंतुलित हो जाता है, इसलिए आंखें प्रभावित होती हैं।

सुबह उठकर मुंह में पानी भरें

रोज सुबह उठकर टॉयलेट जाने से पहले या बाद में मुंह में पानी भरें और कुछ सैकंड्स तक होल्ड करें। इस दौरान आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। अब कुल्ला कर दें और इस प्रक्रिया को दो से 3 बार दोहराएं।

त्रिफला वॉटर का उपयोग करें

त्रिफला वॉटर आई वॉश आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह न केवल आपके आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बल्कि आंखों की चमक में भी सुधार करता है। खासतौर से थकी हुई आंखों को आराम देने का यह बेहतरीन तरीका है।

स्वस्थ आंखों के लिए षटकर्म करें

आयुर्वेद में शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने ,उसे मजबूत बनाने और रोगमुक्त बनाने के लिए 6 प्यूरीफिकेशन टेकनीक के बारे में बताया गया है। इनमें से नेती और त्राटक सूखी आंखों और आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे आयुर्वेदिक उपाय के रूप में काम करते हैं। बता दें कि त्राटक षटकर्म आंख का व्यायाम है जिसमें किसी भी बिंदु पर आंखों को स्थिर करके निरंतर देखना होता है।

बरतें ये सावधानियां

- आंखों की देखभाल के दौरान कभी भी बहुत तेज गर्म या फिर बर्फ के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- अचानक तापमान में हुए परिवर्तन से बचने का प्रयास करें।
- अगर आपका शरीर गर्म हो रहा है या आप पसीने से तर हैं, तो अपने चेहरे और आंखों पर पानी के छीटें मारने से पहले 10 मिनट तक इंतजार करें। जब तक आपकी बॉडी सही तापमान में एडजस्ट न हो जाए, छीटें मारने से बचें।
- सुबह-शाम चेहरे पर पानी के छीटे मारें
- 10-15 बार अपनी आंखों और चेहरे पर ठंडे या फिर नॉर्मल पानी के छीटें मारें। इस प्रक्रिया को आप तब भी दोहराएं , जब शाम को काम से वापस घर लौटें। ऐसा करने से आंखों को बहुत आराम मिलेगा।

स्वस्थ आंखों के लिए फायदेमंद है अंजन

स्वस्थ आंखों के लिए अंजन का उपयोग बहुत फायदेमंद है। अंजना एक आयुर्वेदिक दवा है, जिसे आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पलकों के अंदरूनी हिस्से पर लगाते हैं। बता दें कि अंजना जड़ी-बूटियों से बना एक गाढ़ा आईलाइनर है। इसे कोलिरिसम भी कहते हैं। इसका उपयोग आंखों की रोशनी बढ़ाने और आंख से जुड़ी अन्य बीमारियों के लिए किया जाता है। हालांकि, यह काजल की तरह दिखता है, लेकिन इससे काफी अलग है। इसे मिनरल्स और जड़ी- बूटियों को पीसकर पेस्ट के रूप में तैयार किया जाता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए इनकी देखभाल करना बेहद जरूरी है। उम्मीद है यहां एक्सपर्ट द्वारा बताए गए तरीकों से आपको आंखों की सही देखभाल करने में मदद मिलेगी।

वायु प्रदूषण और रोड ट्रैफिक से पड़ता है सेहत पर बुरा असर

वायु प्रदूषण और रोड ट्रैफिक से हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन कई दफा हम इसे नजरअंदाज करते हैं। शोध में पता चला है कि ये दोनों पर्यावरण हार्ट फेलियर का भी एक कारण हैं।

देश में दिवाली आने वाली है और इस माह में लोगों द्वारा की जाने वाली आतिशबाजी के कारण वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाता है और स्मॉग का रूप ले लेता है। इस तरह के पॉल्युटिड स्मॉग में धूल और वायु प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड, ज्वलनशील कार्बनिक यौगिक आदि हानिकारक मिश्रण रहते हैं। जो खांसी, गले में खराश, छाती में जलन, स्किन डिजीज, फेफड़ों के संक्रमण, आंख व नाक में एलर्जी के अलावा इम्यून सिस्टम को भी कमजोर बनाते हैं। हाल ही में वायु प्रदूषण पर एक शोध आया है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नए शोध के अनुसार, वायु प्रदूषण और सड़क यातायात के शोर के संपर्क में आने से हृदय गति रुकने का खतरा बढ़ सकता है। शोध का रिजल्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक ओपन-एक्सेस जर्नल 'जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन' में प्रकाशित किया गया था। इसलिए आपको वायु प्रदूषण से खुद को सेफ रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।

वायु प्रदूषण पर शोध

नए रिसर्च के विश्लेषण में शोधकर्ताओं ने 15 से 20 साल के पीरियड में लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट इंपैक्ट को लेकर हर्ट फेलियर की जांच की। डेनमार्क में महिला नर्सों पर हुए शोध में एयर पॉल्यूशन और रोड ट्रैफिक हर्ट फेलियर की मुख्य वजह पाया गया। बता दें कि शोध में जिन महिलाओं को लिया गया था उनकी उम्र 44 वर्ष और उससे अधिक थी। प्रतिभागियों को 1993 और 1999 में भर्ती किया गया था और जब उन्होंने नामांकन किया, तो हर महिला ने बॉडी मास इंडेक्स, लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे धूम्रपान, शराब का सेवन, शारीरिक गतिविधि और आहार संबंधी आदतों के अलावा अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में भी पूरी जानकारी दी थी। इन सभी प्रतिभागियों को डेनिश नेशनल पेशेंट रजिस्टर से लिंक करने के 20 साल के बाद हार्ट फेलियर के बारे में पता चला जिनका बाद में इलाज भी हुआ और इसके रिकॉर्ड भी हैं।

दिल के लिए ज्यादा खतरनाक है वायु प्रदूषण

डेनमार्क स्थिति कोपेहेगन यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े असिस्टेंट प्रोफेसर और शोध को लीड करने वाले ऑथर ने कहा कि स्टडी में पाया गया है कि तीन वर्षों में रोड ट्रैफिक का शोर 12 फीसदी हार्ट फेलियर के खतरे का कारण बना। उन्होंने आगे कहा, हम आश्चर्यचकित थे कि कैसे दो पर्यावरणीय कारक - वायु प्रदूषण और सड़क यातायात शोर ने एक साथ हृदय गति रुकने का जोखिम बढ़ा दिया है। शोध में पता चला है कि रोड ट्रैफिक की तुलना में एयर पॉल्युशन हर्ट फेलियर के खतरे की मजबूत वजह बना। हालांकि, इन हर्ट फेलियर वाली 30 प्रतिशत नर्सों में हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी।

सांस लेने में तकलीफ

वायु प्रदूषण की वजह से बुजर्ग लोगों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एयर पॉल्युशन के कारण बुजुर्गों के शरीर के कई अंग धीमी गति से कार्य करते हैं और इसी तरह का हाल फेफड़ों का रहता है। क्योंकि लंग्स प्रदूषित हवा को सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाते हैं जिस वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है।

आंखों में परेशानी

वायु प्रदूषण के चलते कई बार बच्चों से लेकर बुजुर्गों की आंखों में भी दिक्कतें आती हैं। दूषिक हवा के कण हमारी आंखों में एलर्जी पैदा करने लगते है जिससे कई बार हमें आस-पास की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। साथ ही धूल मिटटी से आंखों में खुजली भी होती है।

सेहत संबंधी दिक्कतें

बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है जिसकी वजह से उनको वायू प्रदूषण और रोड ट्रैफिक से उनका दम घुटने लगता है। वे इस वातावरण को आसानी से हैंडल नहीं कर पाते। इसके चलते कई दफा, छींकआना, छाती में जलन, स्किन डिजीज, फेफड़ों के संक्रमण और गले में खराश जैसी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

साइलेंट किलर है तनाव, इसे गंभीरता से लेना है बहुत जरूरी

मेंटल हेल्थ एक पुराना विषय रहा है, लेकिन अब कोरोना के बाद यह और ज्यादा घातक हो गया है। अब इसे गंभीरता से लेकर इस पर बात करना जरूरी है। कोरोना ने कई तरह के मानसिक रोगों को जन्म दिया है

आज के दौर में हर शख्स अपनी जिंदगी में स्ट्रेस से गुजरता है। स्ट्रेस को आजकल एक कॉमन परेशानी के रूप में देखा जाता है और यही सबसे बड़ी गलती है। 2020 में आए कोविड 19 ने सोशल और इकोनॉमिक तौर पर काफी बदलाव लाया है। लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी गवां दी, यहां तक की एक दूसरे से मिलना-जुलना भी दूभर हो गया था। आज जहां 2021 में कोविड 19 को 2 साल हो गए हैं और आज भी मानव जाति इस विपदा से उबरने की कोशिश में है। कई देश आज भी इस वायरस के नए स्ट्रेन से लड़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ने ये चेतावनी जारी की है कि कोरोनावायरस का मेंटल हेल्थ पर काफी लंबे समय तक असर होता रहेगा। आज लोगों में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी कई समस्या बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। इस पैंडेमिक के दौरान मेंटल हेल्थ पर गहरा असर पड़ा है। 2020 में माइसेंसी द्वारा एक सर्वे के आधार पर ठट्ठ के 75 प्रतिशत और एशिया के 33 प्रतिशत एम्प्लॉय में बर्न आउट के लक्षण दिखे हैं। यूरोपियन देशों में भी पैंडेमिक फैटिग के लेवल में बढ़ोतरी हुई है।

जिन लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत खराब रेट दिया है, उनकी मात्रा पैंडेमिक आने के बाद तीन गुना बढ़ गई है। ओरेकल और वर्क प्लेस इंटेलिजेंस जैसी कंपनियों द्वारा एक हालिया सर्वे जिसमें 11 देशों के 12000 लोगों ने भाग लिया ये दर्शाता है कि मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव में एम्प्लॉय के बदले ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज पाए गए हैं। 53% ने माना की उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज पैंडेमिक के शुरू होते ही शुरू हो गए थे। इसी कड़ी में 5 में से 4 मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव यानी लगभग 85% ने माना कि उन्हें काम को पूरा करने में दिक्कत आई। इसके कुछ कारण हैं जैसे घर से काम करने के दौरान नई तकनीक को समझने और उसका उपयोग करने में परेशानी और दूसरा यह कि ऑफिस के माहौल से दूर साथ बैठकर काम करने और कोलेबरेट करने की जगह घर से काम करना।

क्या कहती है रिपोर्ट?

इस कड़ी में लगभग 39% लोगों को घर से वर्चुअली काम करने में दिक्कत आई। वहीं 34% को वर्क कल्चर के ना होने की कमी खली। वहीं 29% लोगों को नई तकनीकों को समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ कंपनी के सीनियर अधिकारी वर्कप्लेस पर मेंटल हेल्थ और हेल्थी वर्क कल्चर को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं आज भी मेंटल हेल्थ को एक स्टीरियोटाइप के तौर पर देखा जाता है। कंपनी में ओपन कम्युनिकेशन और सपोर्ट की कमी खलती है। कंपनी के लीडर को अपने स्टॉफ को न सिर्फ इंस्पायर करना चाहिए ताकि वे अपनी बात को खुलकर शेयर कर सकें, बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर वे कोच या थेरेपिस्ट से मदद भी ले सकें। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नौर नहीं करना है, अगर तनाव से संबंधी कोई भी लक्षण नजर आता है तो तत्काल डॉक्टर से मिलना है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते।

जान भी ले सकती है लौकी

लौकी का सेवन करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसे कई प्रकार से खा सकते हैं। सब्जी, जूस, खीर, कलाकंद, पराठे सहित अन्य तरीकों से इसका सेवन किया जा सकता है। इसका सेवन करने से कब्ज और गैस की समस्या में राहत मितली है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम,

कड़वी लौकी का सेवन करने से आपकी जान पर बात बन सकती

नौबत आ जाती है। इसलिए भूलकर भी कड़वी लौकी का सेवन नहीं करें। लौकी का जूस बनाने से पहले इसे जरूर टेस्ट करें। अगर वह कड़वी लगती है तो इसका सेवन नहीं करें। कड़वी विषैली लौकी का सेवन करने के नुकसान- बेचैनी, घबराहट, ब्लड प्रेशर की समस्या, उल्टी होने लगती है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार अंगों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में अंग फैल भी हो सकते हैं। इसलिए भूलकर भी लौकी को टेस्ट किए बिना इसका प्रयोग नहीं करें। कड़वी लौकी की पहचान उसे चखकर की जा सकती है। बता दें कि इसे पकाने पर भी कड़वापन खत्म नहीं होगा। कड़वी लगने

डिफेंस सिस्टम विकसित कर लेती है। जिससे उसमें केमिकल विकसित हो जाता है। तो कई बार तापमान कम ज्यादा होने पर भी यह बदलाव होने लगते हैं। इतना ही नहीं पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर भी ऐसा हो सकता है।

उपेक्षा के शिकार बुजुर्गों की लें सुध

पिछले महीने एक बुजुर्ग दंपती की खबर खूब चर्चित हुई। यह घटना थी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की, जिसमें बेटे-बहू की उपेक्षा और उत्पीड़न से परेशान बुजुर्ग ने नहर में छलांग लगा दी। पति को बचाने के लिए पत्नी भी नहर में कूद गई और नौ किमी तक पति का हाथ थामकर तैरती रही, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाई। इस घटना के कुछ ही दिन बाद छत्तीसगढ़ के जशपुर से खबर आई कि एक बेटे ने कुल्हाड़ी से काटकर मां के टुकड़े कर डाले। एक अन्य खबर के अनुसार उपेक्षा से त्रस्त पिता ने बेटियों के अपमान और लालच से तंग आकर चार करोड़ रुपये की संपत्ति मंदिर को दान दे दी। ऐसी तमाम घटनाएं समाज में आए दिन घटित हो रही हैं। भारतीय समाज में आज भी श्रवण कुमार आदर्श माने जाते हैं। मां-बाप की कामना होती है कि उनका बेटा श्रवण कुमार हो, लेकिन श्रवण कुमार भारतीय परंपरा से अब खत्म से होते दिखते हैं। बुजुर्गों की बदहाल स्थिति और बढ़ते वृद्धा आश्रम इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यह रुझान समय के साथ और बढ़ता ही जा रहा है। भारत में वृद्धों की सेवा और रक्षा के लिए कई कानून बने हैं। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2007 में वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम लागू किया। भारत के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रजनन दर घटी है, जिसके कारण 0-14 वर्ष की आबादी घट रही है और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। केरल सरकार ने इसी बढ़ती आबादी और बुजुर्गों के जीवन की समस्याओं के मद्देनजर वृद्ध आयोग का गठन किया, जो सराहनीय कदम है, लेकिन दुर्भाग्यवश तमाम सुविधाएं, नियम-कानून कागजों में ही ज्यादा सीमित हैं। पिछले कुछ वर्षों में बुजुर्गों से जुड़े अलग तरह के मामले सामने आए। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग विधवा अथवा विधुर थे और अकेले थे। पति या पत्नी का सहारा ऊपर वाले ने छीन लिया था और बच्चों का किस्मत ने। जिस बुढ़ापे के लिए बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा किया था, उन्होंने ही बुढ़ापे में जीना मुश्किल कर दिया और वह भी थोड़ी सी संपत्ति के लिए। दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाओं में बुजुर्ग नियमानुसार मदद मांगने जाते हैं तो उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है। कई मामलों में बुजुर्गों ने सबसे पहले वन स्टाप सेंटर में शिकायत की। वहां अदालत की तर्ज पर तारीखें मिलने लगीं। तारीख पर दोनों पक्षों को बुलाया जाता। थक-हार कर शिकायत मुख्यमंत्री ग्रिवांस सेल, एसडीओ, कलेक्टर, एसपी, डीजीपी, कमिश्नर, मानवाधिकार आयोग, डीएलएसए और हेल्पलाइन नंबर पर की गई। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को भी सूचना भेजी गई, जहां से जिलाधिकारी को कार्रवाई करके रिपोर्ट भेजने का निर्देश मिला, किंतु सब व्यर्थ रहा। अचंभे की बात यह है कि कई अधिकारियों और पुलिस वालों को भी वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम की जानकारी नहीं होती। एक अधिकारी सिर्फ इतना जानते थे कि 10 हजार रुपये भरण-पोषण के लिए के लिए दिए जाते हैं, जबकि इसके तहत माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत पर संतानों पर दंड, जुमार्ने के साथ संपत्ति से बेदखल करने और हस्तांतरित संपत्ति वापस लेने का भी प्रविधान है, लेकिन इसका शायद ही इस्तेमाल होता है। शारीरिक और आर्थिक असमर्थता के बीच अधिकारियों और थाने के चक्कर लगा-लगाकर कई बुजुर्ग टूट जाते हैं और अवसाद में जीवनयापन करने लगते हैं। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये वही बुजुर्ग हैं, जिनकी कहानियां बच्चों में संस्कारों की नींव रखती थी, जिनकी लोरियां उन्हें सुखद नींद में परियों के देश का भ्रमण कराती थी। माता-पिता जब डांटते, तब दादा-दादी का ही आश्रय होता था। एकल परिवार की संकल्पना ने बच्चों से बुजुर्गों का सहारा छीन लिया और बुजुर्गों से छत। भागम भाग के बीच संतानें बुजुर्गों को समय नहीं दे पातीं, जिससे उनमें अकेलापन, अवसाद बढ़ रहा है। साथ ही हिंसात्मक घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। माता-पिता अपनी संतानों के खिलाफ शिकायत नहीं करना चाहते। ऐसा करते भी हैं तो तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती, जब तक कोई अनहोनी घटना नहीं घट जाती। प्रशासन का रुख वृद्धों के मनोबल को तोड़ देता है। अंततः वे वृद्धाश्रम जाने को मजबूर हो जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। बुढ़ापे में आर्थिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। सरकारी नौकरी वाले तो पेंशन से जी लेते हैं, परंतु वृद्धावस्था पेंशन से गुजारा मुश्किल होता है। अपने देश में वृद्धाश्रम और डे केयर सेंटर भी कम हैं और जो हैं, उनमें से ज्यादातर बदहाल हैं। बुजुर्गों के संरक्षण संबंधी मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। इनका पालन नहीं करने वालों पर कठोर सजा का प्रविधान हो। बुजुर्गों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनें और घर पर सेवा मिले। इसके अलावा, बुजर्गों को वृद्धाश्रम भेजने पर जोर न देकर उनके अधिकारों को संरक्षित करने की पहल हो। इस सबके साथ चेतनाशून्य समाज का जागना भी बहुत जरूरी है।

हिंसा करने के बाद भी दूध से सिंचित करने की मानसिकता

ANALYSIS

✍ डॉ. मयंक चतुर्वेदी

ईद-ए-मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान औरंगजेब की तस्वीर पर दूध चढ़ाया गया। धाराशिव में औरंगजेब के समर्थन में लगे नारों के वीडियो पहले ही सामने आ चुके थे। हालांकि इस घटना को कुछ वक्त हो गया है, पर अब नई घटना उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा के हालिया बयान के माध्यम से घटी है। वह कहती हैं, हम कई अच्छे राजाओं को याद रखते हैं और कुछ औरंगजेब जैसे भी थे, जो एक कुशल प्रशासक था। स्वभाविक है कि औरंगजेब को कुशल प्रशासक कहने का विरोध होना चाहिए, वह हुआ भी। छात्रों के बीच राष्ट्रीय चेतना की अलख जगानेवाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने उनके इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। एबीवीपी की ओर से कहा गया, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को ऐतिहासिक तथ्यों पर टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यह विद्यार्थियों और इतिहास प्रेमियों के लिए अनुचित है। विकसित भारत 2047 के लिए रोडमैप विषय पर वक्तव्य दे रही थीं और औरंगजेब को कुशल प्रशासक बता रही हैं। जिस आदमी का वजूद ही गैर मुसलमानों (हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन एवं अन्य) के विरोध पर टिका हो, वह कुशल प्रशासक कैसे हो सकता है। वैसे व्यंग्य करने लिए यह बात अच्छी है, किंतु क्या वास्तव में ऐसा ही है। यदि हम औरंगजेब के शासनकाल को देखते हैं, तो ध्यान आता है कि शायद ही उसने कभी अच्छा काम किया हो।

अभी हाल ही में दो घटनाएं देश में औरंगजेब से जुड़ी घटी हैं। महाराष्ट्र के अकोला से क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के समर्थन में नारे लगाने और उसकी तस्वीर पर दूध चढ़ाने का वीडियो सामने आया। ईद-ए-मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान औरंगजेब की तस्वीर पर दूध चढ़ाया गया। धाराशिव में औरंगजेब के समर्थन में लगे नारों के वीडियो पहले ही सामने आ चुके थे। हालांकि इस घटना को कुछ वक्त हो गया है, पर अब नई घटना उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा के हालिया बयान के माध्यम से घटी है। वह कहती हैं, हम कई अच्छे राजाओं को याद रखते हैं और कुछ औरंगजेब जैसे भी थे, जो एक कुशल प्रशासक था। स्वभाविक है कि औरंगजेब को कुशल प्रशासक कहने का विरोध होना चाहिए, वह हुआ भी। छात्रों के बीच राष्ट्रीय चेतना की अलख जगानेवाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने उनके इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। एबीवीपी की ओर से कहा गया, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को ऐतिहासिक तथ्यों पर टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यह विद्यार्थियों और इतिहास प्रेमियों के लिए अनुचित है। विकसित भारत 2047 के लिए रोडमैप विषय पर वक्तव्य दे रही थीं और औरंगजेब को कुशल प्रशासक बता रही हैं। जिस आदमी का वजूद ही गैर मुसलमानों (हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन एवं अन्य) के विरोध पर टिका हो, वह कुशल प्रशासक कैसे हो सकता है। वैसे व्यंग्य करने लिए यह बात अच्छी है, किंतु क्या वास्तव में ऐसा ही है। यदि हम औरंगजेब के शासनकाल को देखते हैं, तो ध्यान आता है कि

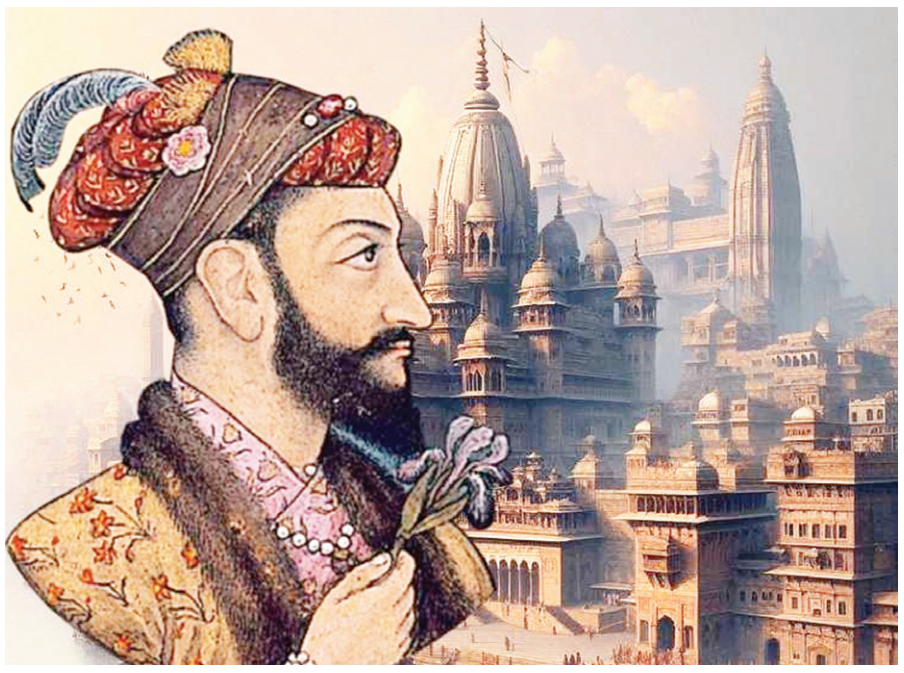

शायद ही उसने कभी अच्छा काम किया हो। भारत के मध्यकालीन इतिहास में औरंगजेब (1618-1707) का व्यक्तित्व सबसे विवादास्पद है। उसके शासनकाल में धार्मिक असहिष्णुता, हिंदू मंदिरों के विध्वंस, जजिया कर की पुनः स्थापना, सिख और मराठा प्रतिरोध के दमन, कला-संस्कृति पर रोक तथा अपने पिता और भाइयों के साथ विश्वासघात जैसी घटनाएं हुईं। उसकी नीतियों ने भारतीय समाज में गहरी संप्रदाय खाई उत्पन्न कर दी (सतीश चंद्र, मुगल भारत : सुलतानत से मुगल साम्राज्य तक, 2005, पृ. 120)। शाहजहां का प्रिय दारा शिकोह था, जो हिंदू-मुस्लिम एकता और सूफी परंपरा का समर्थक था। दारा ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया और हिंदू-इस्लामी विचारधारा के संगम की संभावना प्रस्तुत की (दारा शिकोह, सिर्र-ए-अकबर, 1657)। औरंगजेब को दारा का यह दृष्टिकोण विधर्म प्रतीत हुआ। 1658 में समरगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा को परास्त किया। 1659 में उस पर कुफ्र का आरोप लगाकर उसे दिल्ली लाया गया और मृत्यु दंड दे दिया। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि दारा को दिल्ली की गलियों में अपमानित कर घुमाने के बाद उसका वध किया गया और सिर शाहजहां को भेजा गया (जदुनाथ सरकार, औरंगजेब का इतिहास, खंड 2, 1912, पृ. 152-160)। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां तक को 1658 से लेकर 1666 में मृत्यु तक आगरा किले में कैद रखा। राजनीतिक सत्ता संभालने के साथ ही औरंगजेब ने धार्मिक नीतियों में भी बदलाव आरम्भ किया। औरंगजेब के निर्णयों में शरिया के कड़वे रूप की झलक मिलती है। प्रारंभिक वर्षों में वह कुछ हद तक व्यावहारिक भी दिखा, पर समय के साथ उसकी धार्मिक नीतियां कठोर होती गईं (सतीश चंद्र, मुगल भारत, पृ. 290-295)। उसने अपनी शासन नीति का दबाव बनाने के लिए धार्मिक वाद-प्रतिवाद और सार्वजनिक इस्लामिक चिह्नों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ऐतिहासिक रूप से मंदिर विध्वंस और धार्मिक स्थलों के प्रतिस्थापन की घटनाएं औरंगजेब के समय ही हुईं। औरंगजेब ने मंदिर विध्वंस की नीति को राज्य नीति का अंग बना दिया। 1669 में उसने काशी के विश्वनाथ मंदिर को गिरवाया और वहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया (सतीश चंद्र, वही, पृ. 286)। 1670 में मथुरा का केशव राय मंदिर ध्वस्त कर उसकी जगह ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ (जदुनाथ सरकार, औरंगजेब का इतिहास, खंड 3, पृ. 102)। रिचर्ड एम. ईटन के अनुशीलन के अनुसार यह केवल लोकोपयोगी राजनीति नहीं थी, बल्कि मंदिर विध्वंस को धार्मिक (इस्लामिक) श्रेष्ठता के संदेश के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति भी थी, जिससे स्थानीय समाजों में भय और अवसाद दोनों का वातावरण बना। मध्य क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात में भी प्रमुख मंदिर ध्वस्त किए गए। इससे हिंदू समाज में गहरी निराशा और विद्रोह की भावना पनपी। अकबर ने जिस जजिया कर को अपने शासनकाल में लगाया। जजिया यानी वो कर जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था, इसलिए कि वे मुसलमान नहीं हैं, इसके बाद भी वे मुस्लिम सत्ता वाले राज्य में रहते हैं। गैर मुस्लिम नागरिकों को संज्ञा दी गई थी (जिम्मी) की, इन्हीं से ये वसूल किया जाता था। इसी के आधार पर गैरमुस्लिमों को इस्लामिक राज्य में रहते हुए अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन इस कर को अपने तमाम अनुभवों के बाद अकबर ने ही 1564 में हटा दिया था। जहांगीर और शाहजहां ने भी इसे लागू नहीं किया। लेकिन, 1679 में औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते ही इसे पुनः चालू किया। यह कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित करने जैसा था। औरंगजेब ने संगीत और नृत्य जैसी कलाओं पर प्रतिबंध लगाया। दरबार से नर्तकों और गायकों को निकाल दिया गया। प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की संख्या घटाई गई। जदुनाथ सरकार के अनुसार, औरंगजेब ने अपने अंतिम वर्षों में कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया और हिंदुओं के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। भारतवर्ष में यदि देखा जाए तो औरंगजेब के अत्याचारों का सबसे प्रबल प्रतिरोध मराठों ने किया। शिवाजी महाराज (1627-1680) ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया। उन्होंने मुगल सेनाओं को बार-बार पराजित किया। मराठों की छापामार रणनीति से औरंगजेब अपने जीवनकाल में मरने के पहले तक परेशान रहा।

गजवा-ए-हिंद का सपना और महबूब आलम की गिरफ्तारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के बिहार प्रदेशाध्यक्ष महबूब आलम की गिरफ्तारी की है। इसे उस गहरी साजिश के तहत पकड़ा गया है, जो भारत को भीतर से तोड़ने के लिए वर्षों से बुनी जा रही थी। वस्तुतः महबूब आलम, कटिहार जिले का निवासी है। वह 26 आरोपियों में से एक है जिन पर 2022 में फुलवारीशरीफ में दर्ज आपराधिक आतंकी साजिश का आरोप है। वह इस मामले में गिरफ्तार किए गए 19वें व्यक्ति के रूप में एनआईए के हत्थे चढ़ा। उसका काम था संगठन के कैडरों तक विदेशी फंड पहुंचाना, युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर लगाना और उस नेटवर्क को मजबूत करना, जिसका लक्ष्य था भारत को वर्ष 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बना देना। यहां यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या यह केवल एक संगठन की हद तक सीमित है या फिर इसके पीछे कहीं अधिक गहरी, संगठित और अंतरराष्ट्रीय स्तर की योजना काम कर रही है, क्योंकि जुलाई 2022 में फुलवारीशरीफ से बरामद आठ पन्नों का दस्तावेज इंडिया विजन 2047 इस सवाल का उत्तर देता है। यह दस्तावेज भारत की संप्रभुता को समाप्त कर इस्लामी शासन स्थापित करने का खाका था। इसमें साफ लिखा मिलता है कि यदि केवल दस प्रतिशत मुस्लिम आबादी भी साथ आ जाए तो बहुसंख्यक समाज को दबाकर सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है। इस साक्ष्य में चार चरणों का उल्लेख किया गया मिला है। पहला- युवाओं को संगठन से जोड़कर कट्टरपंथ की ओर मोड़ना। दूसरा- उन्हें हथियार चलाने और मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देना। तीसरा- पुलिस, सेना और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में अपने वफादार स्थापित करना और चौथा- विदेशी सहयोग से सीधे संघर्ष में उतरना। इस दस्तावेज में प्रधानमंत्री पर हमला करने की योजना बनाने और उसे कैसे अंजाम देना है, इस तक दर्ज मिला। यहां हो सकता है, किसी को लगे कि लेखक ये क्या बेकार की बातें लिख रहा है, यह तो कल्पनालोक है, किंतु यदि कोई ऐसा सोच रहा है तो वह हकीकत को स्वीकारना नहीं चाहता, यही कहना होगा। वस्तुतः यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। पीएफआई लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में था। शुरूआत में उसने खुद को सामाजि और शैक्षिक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि उसकी गतिविधियों पर संदेह न हो। परंतु, धीरे-धीरे इसकी असली तस्वीर सामने आती गई। 2022 में एनआईए और ईडी द्वारा 17 राज्यों में की गई छापेमारी ने इस संगठन का असली चेहरा उजागर कर दिया। इन छापों में हथियार प्रशिक्षण मॉड्यूल, बम बनाने के मैनुअल और हिट लिस्ट बरामद हुईं। इसके बाद ही सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े आठ संगठनों पर पाँच साल का प्रतिबंध लगाया। इसमें आ इंडिया इमाम्स काउंसिल, कैंपस फ्रंट आफ इंडिया और रहाब इंडिया फाउंडेशन जैसे संगठन शामिल हैं। महबूब आलम की गिरफ्तारी से जो बातें सामने आईं, वे बताती हैं कि उसका काम केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था। वह गल्फ देशों से हवाला के जरिए आने वाले धन को नेटवर्क तक पहुंचाने में सक्रिय था। यह धन युवाओं की भर्ती, उन्हें ट्रेनिंग देने और प्रोपेगेंडा चलाने में खर्च होता था। इंडिया विजन 2047 दस्तावेज में तुर्किये का विशेष उल्लेख था कि संघर्ष की स्थिति में वह भारतीय मुस्लिमों की मदद करेगा। इसका सीधा अर्थ है कि यह केवल भारत के भीतर की समस्या नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क का हिस्सा है। गजवा-ए-हिंद की विचारधारा इसी नेटवर्क का ईंधन है। इस अवधारणा का अर्थ है, भारत की धरती पर इस्लामी शासन की स्थापना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कट्टरपंथी गुट इस विचार को वर्षों से बढ़ावा देते आए हैं। आईएसआईएस और अलकायदा ने भी इसका इस्तेमाल भारतीय युवाओं को बरगलाने के लिए किया। सोशल मीडिया पर हजारों संदेश फैलाए गए, जिनमें भारत को अगला युद्धक्षेत्र बताया गया। महबूब आलम और उसके जैसे लोग इसी विचारधारा के वाहक हैं। यहां यह देखना आवश्यक है कि यह नेटवर्क कितना व्यापक था। बिहार में महबूब आलम और सज्जाद आलम, केरल में मुहम्मद मुबारक, महाराष्ट्र में डॉ. अदनान अली सरकार और तमिलनाडु में मुहम्मद अखलथुर जैसे नाम सामने आए। कहीं हिट लिस्ट तैयार की जा रही थी, कहीं युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो कहीं विदेशी फंडिंग और प्रचार-प्रसार का काम हो रहा था। एक तरह से देखा जाए तो यह पूरे देश को जकड़ने की साजिश थी। आंकड़े बताते हैं कि खतरा कितना गंभीर है। 2014 से 2021 तक आईएसआईएस से जुड़े 37 मामले दर्ज हुए हैं और 168 लोग गिरफ्तार हुए। 500 से अधिक समर्थक पकड़े गए, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। केवल फुलवारीशरीफ केस में ही जैसा बताया गया कि 26 आरोपियों पर चार्जशीट दायर हुई । 2022 की छापेमारी में 100 से अधिक पीएफआई कार्यकर्ता पकड़े गए। यह कोई छिटपुट घटना नहीं, एक व्यापक पैटर्न के रूप में दिखाई दिया है। आज चिंता यह है कि भारत का लोकतंत्र विविधता और सहिष्णुता पर टिका है। लेकिन, जब कोई संगठन युवाओं को यह विश्वास दिलाता है कि उनकी अस्मिता केवल इस्लामी शासन से सुरक्षित रह सकती है, तो यह केवल संविधान पर हमला नहीं करता, बल्कि करोड़ों भारतीय मुसलमानों को भी कठघरे में खड़ा कर देता है जो शांति और प्रगति में विश्वास रखते हैं। यह स्थिति खतरनाक है, क्योंकि इससे सामाजिक ताने-बाने में दरार पड़ती है। अब इस मामले में भले ही सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कठोर कार्रवाई की, परंतु ध्यान में आता है कि सिर्फ प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है। फंडिंग के स्रोतों पर कड़ी निगरानी, साइबर स्पेस पर नजर और युवाओं को सकारात्मक दिशा देना अनिवार्य है। स्थानीय स्तर पर इस्लामिक मजहबी नेताओं और शिक्षाविदों को भी चाहिए कि वे सुधार के लिए आगे आएं ताकि कट्टरपंथी विचारधाराओं का प्रतिकार हो सके। महबूब आलम की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से पनप रही वैचारिक घुसपैठ है। यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, इससे भी कहीं आगे की राष्ट्रीय अस्मिता की लड़ाई है।

Social Media Corner

सच के हक में...

भारत माता के महान सपूत और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन। देश को समृद्धि की राह दिखाने वाले उनके राष्ट्रवादी विचार और अंत्योदय के सिद्धांत विकसित भारत के निर्माण में बहुत काम आने वाले हैं।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के प्रणेता, महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर सविनय नमन। अपने जीवन एवं विचारों से भारतीय समाज को समग्र विकास और सामाजिक समरसता का मार्ग दिखाने वाले दीनदयाल जी ने राष्ट्रीय एकता, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान ने देश को वैचारिक दिशा प्रदान की। उनकी दर्शनशास्त्रीय कृति एकात्म मानववाद भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर आधारित एक ऐसी विचारधारा है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। पंडित जी ने अंत्योदय का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया, जिसका लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को प्राथमिकता देना है। सादगी, निष्ठा और समाज सेवा का प्रतीक पंडित दीनदयाल जी का जीवन हमें कर्मशीलता और सेवाभाव की प्रेरणा देता है।

(ओम बिड़ला का 'एक्स' पर पोस्ट)

एक और दुष्प्रचार की निकली हवा

इसी वर्ष अप्रैल में जब वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था तो विपक्ष ने इसे घोर असंवैधानिक और मनमाना करार दिया था। कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे मुसलमानों की मस्जिदें-कब्रिस्तान छीनने वाला कानून बता दिया था- ठीक वैसे ही जैसे नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला बताकर उन्हें सड़क पर उतारा गया था और जिसके नतीजे में कई जगह हिंसा हुई थी। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद जैसे ही उसने कानून का रूप लिया, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधानिकता का परीक्षण करने के लिए तैयार मिला, क्योंकि इस कानून को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं दाखिल कर दी गई थीं। अब ऐसा संसद से बने और संशोधित हुए करीब-करीब प्रत्येक बड़े कानून के साथ होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा, राज्यसभा के बाद एक तरह से तीसरे सर्वोच्च सदन की तरह काम करने लगा है। इधर संसद से पारित होकर कोई विधेयक कानून का रूप लेता है, उधर विपक्षी दलों के कुछ नेता और याचिकाबाज वकील सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर उसे चुनौती देने के लिए खड़े मिलते हैं। निःसंदेह सुप्रीम कोर्ट को प्रत्येक कानून की संवैधानिकता परखने का अधिकार है, लेकिन क्या अब हर कानून अमल में आने के पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। तीन कृषि कानूनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर इन कानूनों की संवैधानिकता पर विचार किए बिना ही उनके अमल पर रोक लगा दी थी। यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपने अधिकारों का किया जाने वाला खुला-नग्न अतिक्रमण था। इन कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी समीक्षा के लिए एक समिति गठित कर दी थी, लेकिन जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसने उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह कृषि कानून विरोधी आंदोलन के नेताओं की ओर से राजमार्ग रोकने के मामले में भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। अंततः दुष्प्रचार के चलते ऐसी परिस्थितियां बनीं कि मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने पर बाध्य हुई। इससे किसानों का कितना भला हुआ, यह किसान नेता ही जानें। इन कानूनों को लेकर यह अफवाह फैलाई गई थी कि इनके जरिये किसानों के खेत छीने जाएंगे। चूंकि ये कानून अमल में ही नहीं आए, इसलिए कथित किसान नेता यह थोथा दावा कर सकते हैं कि अंततः किसानों के खेत छिनने से बच गए, लेकिन सीएए तो लागू हो चुका है। किसी को पता हो तो बताए कि कितने मुसलमानों की नागरिकता छिनी। नागरिकता, खेत, कब्रिस्तान या फिर और कुछ छीने जाने का शोर मचाने के लिए किसी नए कानून का निर्माण या फिर उसमें संशोधन किया जाना ही आवश्यक नहीं। अभी हाल में जब चुनाव आयोग की ओर से बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई तो तत्काल यह शोर मचा कि इसका उद्देश्य दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के वोट छीनना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देकर विपक्षी दलों और साथ ही लोकतंत्र के स्वयंभू चैंपियनों के इस दुष्प्रचार की हवा निकाल दी कि चुनाव आयोग बिहार के बेचारे लोगों के वोट छीनने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सभी मान्यता प्राप्त दलों को इस मामले में पक्षकार बनाया और उन्हें इसके लिए बाध्य किया कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लें। मरता क्या न करता, वे बेमन से ही सही, यह काम कर रहे हैं। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर पूरी तरह रोक लगाने से इन्कार कर दिया। उसने अपने अंतरिम फैसले में इसके चंद प्रविधानों पर ही रोक लगाई। यह उल्लेखनीय है कि उसने संशोधित कानून में वक्फ बाई यूजर के प्रविधान को खत्म करने को मनमाना नहीं माना।

शब्द और भावना

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 ने मुस्लिम धार्मिक औकाफ, जिसमें देशभर में काफी जमीनें शामिल हैं, को नियंत्रित करने वाले 1995 के वक्फ अधिनियम को संशोधित किया। इस संशोधन अधिनियम पर 15 सितंबर को अपना फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फूंक-फूंक कर कदम रखा। शीर्ष अदालत ने कई विवादास्पद प्रावधानों को फिलहाल स्थगित कर दिया, लेकिन संवैधानिकता और अन्य चिंताओं के आधार पर पूरे अधिनियम को ठंडे बस्ते में डालने से मना कर दिया। यह एक दुर्लभ उदाहरण बना, जहां अधिनियम के समर्थकों और आलोचकों दोनों ने अदालत के आदेश में अपना नजरिया सही साबित होने का दावा किया। सरकार का मत है कि पुराने वक्फ अधिनियम के तहत कथित दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए ये संशोधन आवश्यक थे, जबकि आलोचक, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, इसे मुस्लिम समुदाय के मामलों में मनमाने हस्तक्षेप के बतौर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस शर्त पर रोक लगा दी है कि पांच साल से इस्लाम का पालन करने वाले मुसलमान ही वक्फ कर सकते हैं। उसने जिला कलेक्टरों में निहित वक्फ संपत्ति विवादों पर न्यायिक निर्णय करने की शक्ति पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या केंद्रीय वक्फ काउंसिल में चार और राज्य बोर्डों में तीन तक सीमित कर दी है, जो पहले क्रमशः 12 और सात तक हो सकती थी। उसने यह भी निर्देश दिया कि जहां तक हो सके वक्फ बोर्डों के सीईओ मुस्लिम होने चाहिए। संशोधित कानून में उपयोग के आधार पर वक्फ (वक्फ-बाय-यूजर) की मान्यता का प्रावधान हटाये जाने को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है, लेकिन यह शर्त लगाई है कि 8 अप्रैल 2025 तक पंजीकृत वक्फ संपत्तियां ऐसे किसी दावे से महफूज रहेंगी। संरक्षित स्मारकों और आदिवासी जमीनों के वक्फ दर्जे पर पाबंदियां संवैधानिक रूप से वैध मानी गईं।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

In Defence of Indian Youth

Two weeks back, youth in Nepal took down their government through massive protests that originated on social media. According to reports, they even held important discussions on the next President on Discord! Whatever you think of the movement, it does take spheres of steel to do it. In Indonesia, protestors set fire to the Parliament building to protest illegal spending by authorities.

In fact, if you look around – all the countries around us are going through a revolution of sorts. In Bangladesh, the people overthrew the government a few months back. In Sri Lanka, the Rajapaksha government was overthrown in 2022. And Pakistan? Well, they have to watch their team lose to India thrice in the span of a month – that is generational trauma, so we shall keep them out of this. But all around us, the youth are up in arms against the system.This led me to find sarcastic social media posts questioning the apparent lethargy of Indian youth. Incendiary posts that questioned where our nation was headed. Of how they are comfortable in their homes and on their smartphones. Memes about youth of other countries revolting, while Indian youth were busy sharing memes. A meta-meme, if you know what I meme!But here's my defence of Indian youth. It's common for older people to judge those younger than them. It's a misapprehension that all human beings nurture. We think we are wiser than those younger than us because we have lived for more years on earth. But that's a rather silly concept. Humans have become apex creatures on earth because every generation is smarter than those that came before them. This is true of the entire world – every generation is smarter, and (surprisingly) kinder than the previous one. If you want proof, just look at the different movements that have taken place over the years. About a hundred years ago, we overthrew kingdoms and created governments run by people. Then, human rights came in. Then came women's rights. Then came animal rights. Then came LGBTQ rights. Every generation expands our understanding of empathy.

It's the fallacy of wisdom that makes us assume we know better than those younger than us. But we just have to look at our parents to notice how obsolete we get as time passes. Which brings me to Indian youth. They are stuck between age-old civilisations and AI innovations. Every generation before them had to deal with crises. Religious riots and nuclear sanctions. Before that, the Emergency and wars. Before that, the Freedom movement.

Today's Indian youth might be the first generation that can pursue their dreams without the fear of the nation crumbling in front of them. On top of that, everything they like is snatched away from them. They liked video games, and PUBG got banned. They got over their insecurities and put themselves out in public through TikTok – but even that got banned. They overcame smoking by switching to vapes – and those got banned. Three years of their peak years were snatched away by Covid-19.

But as a man who's no longer young, I still believe in the youth of India. Maybe Indian revolutions don't happen over petro-bombs, but rather through hashtags and reels. Indian youth revolt against arranged marriage by using dating apps. Against bureaucracy by founding startups. Against strict politicians by making memes. The youth in India have always stood up when it mattered – whether it was the Great Indian Revolt, the freedom movement, or the Emergency. Maybe they're gathering evidence, collecting memes, and making reels. For now, I'd like to give Indian youth the benefit of pout!

Security stakes must spur jointness

India's operational needs are distinctive, but that can't be a pretext to preserve service silos

THE 16th Combined Commanders' Conference was held in Kolkata from September 15 to 17 on the theme of 'Year of Reforms — Transforming for the Future'. In his address at the conference, Prime Minister Narendra Modi instructed the Ministry of Defence to swiftly implement concrete steps to achieve greater jointness, Atmanirbharta and innovation to meet future challenges.Among the decisions taken on promoting jointness, it was announced that the three services agreed to merge their education branches into a single unified Tri-Services Education Corps. Three new joint military stations are to be formed where all facilities of the Army, Navy and Air Force will be combined under a lead service.Several joint doctrines have also been released in recent months. These include cyberspace operations, amphibious operations, special forces operations, airborne and heliborne operations and multi-domain operations. These joint doctrines collectively represent a systematic approach to military transformation, emphasising integration across different warfighting domains while maintaining service-specific expertise and capabilities.It has long been recognised that the Indian military needs to shed its siloed structure and fight as an integrated force. In December 2019, the government created the post of Chief of Defence Staff (CDS) and established the Department of Military Affairs (DMA) within the Ministry of Defence. The DMA was explicitly mandated to drive integration by promoting joint planning in procurement, training and staffing, and to "facilitate restructuring of military commands… by bringing about jointness in operations, including through establishment of joint/theatre commands."

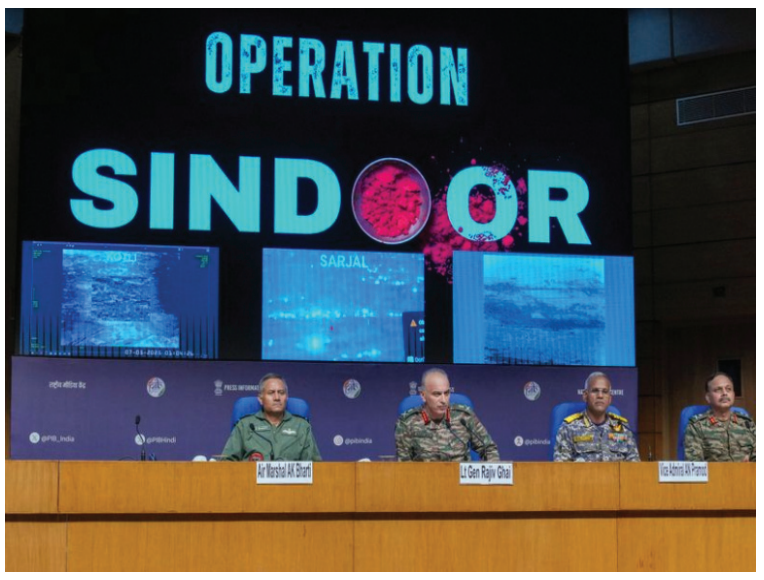

While a lot of effort is going into promoting jointness in the three services, the establishment of the Integrated Theatre Commands remains mired in dissonance, with the Indian Air Force (IAF) pushing back against their creation. Holding only 29 fighter squadrons against a sanctioned 42, the IAF fears that parcelling out its air assets to multiple theatre commands could dilute the effectiveness of airpower. The IAF leadership has argued that air power by its very nature is best used as a flexible, centrally controlled resource that can swing between theatres, an approach that might be compromised under rigid geographic commands.Last month, the IAF Chief, Air Chief Marshal AP Singh, cautioned against rushing the rollout of theatre commands and "disrupting everything to build one structure." Arguing that no new structures are required at the lower level, he suggested the creation of a joint planning and coordination centre in New Delhi, where plans can be made centrally, and execution of tasks is decentralised.

At the event where the Air Force Chief had expressed his reservations, Navy Chief Admiral DK Tripathi said, "The Navy is committed to theaterisation as the ultimate goal." The Army Chief, Gen Upendra Dwivedi, has also asserted that theaterisation of the Indian armed forces will definitely happen, even if it takes time.

These dissonant views raise the larger question of whether any structural changes like the theatre commands are required to move the Indian military to a more efficient warfighting model. Proponents of the status quo cite Operation Sindoor as an example of how coordination and planning at New Delhi, between the service chiefs and the CDS, combined with regular interactions with the political leadership, provides a successful model for future operations. To strengthen coordination, a joint planning structure could be created at New Delhi.

Operation Sindoor has provided many valuable lessons, but treating it as a blueprint for future wars would be an overstretch. This was a brief, tightly controlled operation with limited political objectives. After the initial standoff attacks against terrorist targets, the Army's role was restricted to fire assaults at the Line of Control. The Navy adopted a forward posture to serve as a deterrent but did not actively engage in kinetic operations.

Being primarily a limited air and missile campaign, many critical capacities were not tested during Operation Sindoor. A protracted war involving significant ground or naval combat would demand robust traditional capabilities, including sustained armour and infantry operations, naval operations for sea control and logistics for sustenance over weeks or months. Such operations cannot be executed through coordination at New Delhi but will require a unified command structure in the field that can directly oversee operations in its theatre of responsibility. Even today, the service headquarters primarily serve a staff function, while the responsibility to conduct operations is with the respective command headquarters.It is often stated that India cannot just copy theatre command structures from the US and China, as we have our own unique requirements. While there is some merit in this argument, we also cannot ignore the very valid reasoning behind why these structures were created. The Goldwater-Nichols Act, 1986, which reorganised the US military, was meant to remove the service parochialism and rivalry from the battlefield and address problems of poor quality of collective advice from the Joint Chiefs, cumbersome chains of command and inadequate authority of the warfighting commanders in the field.China's scrapping of the old Military Regions and raising theatre commands marked a shift from ground forces' dominance towards a joint warfighting model integrating all domains under a unified commander. While the Chinese People's Liberation Army (PLA) is still refining its structure, the direction is clearly towards joint commands being essential for the PLA to fight modern, high-tech wars as a unified force. Some of the problems that forced reorganisation in the US and China are common to the Indian military.India's operational needs are distinctive, but that cannot be a pretext to preserve service silos and delay true integration. The debate should not be whether to integrate, but how to tailor integration to India's threat challenges.

Our uniqueness should show up in how we design the integrated architecture. Discussion on this architecture includes the organisational structure of the integrated commands, the command-and-control arrangements, the precise role of the service chiefs in campaign planning, and a clear, rules-based authority for allocating scarce joint resources — especially air and ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance) assets — across theatres. In short, India's specific national security context should shape the model of integration, not justify avoiding it.

Cement legacy with better public goods, not statutory politics

Parties in power prefer the certainty of marble over the challenge of building lasting welfare such as schools that educate generations, hospitals that save lives, or clean water systems that ease daily burdens

The Supreme Court's refusal to allow the Tamil Nadu government to install a statue of former Chief Minister M Karunanidhi in Tirunelveli is not just a local setback. It exposes a persistent national malaise: ruling parties often treat leaders' monuments as their legacy, and as symbols of development and public welfare. From the sprawling elephant parks commissioned by Mayawati in Uttar Pradesh to Gujarat's colossal Statue of Unity, and countless arches, domes, and memorials erected for Nehru, Ambedkar, Shivaji, or regional icons, the pattern is familiar. Every ruling party, irrespective of ideology, succumbs to the politics of perceived permanence. The criticism here is not about cultural monuments or works of art, but specifically about statues and memorials to political leaders—whether crowd-funded or, more troublingly, built with public money. The justification is couched in noble words—honouring leaders, preserving history—but the reality is that statues are instruments of political branding, designed to etch a ruling dispensation's imprint on public space.The real tragedy is in the opportunity cost. Parties in power prefer the certainty of marble over the challenge of building lasting welfare such as schools that educate generations, hospitals that save lives, or clean water systems that ease daily burdens. The tendency is not confined to statues alone. The naming of roads, airports, universities, and welfare schemes after political leaders—an entrenched practice since independence—reflects the same impulse. Like statues, these names perpetuate personality cults, distracting from the institutions' real purpose and the citizens they serve.

Courts and institutions have tried, with mixed success, to temper this tendency. National parties criticise regional ones for "statue mania", but engage in the same practices themselves. To blunt criticism, some even hide behind the images of gods or widely respected national figures. The Madras High Court has suggested 'leaders' parks' to contain statues without obstructing civic life. The Election Commission once directed that statues of Mayawati and the party symbol, the elephant, be covered during campaigns to avoid influencing voters. Mayawati herself once dismissed the notion that statues should only be built posthumously, underscoring how deeply political calculations influence such projects. A country still grappling with poverty, unemployment, and poor infrastructure cannot afford the luxury of the politics of monuments. Remembering leaders is important, but the truest memorial is improving everyday lives.

For a judiciary that stands firm

The SC has been revisiting too many of its own orders, affecting the principle of finality. The rising number of revision, review, and curative petitions is evidence of a malady that affects certainty and adds to pendency. Structural reforms from within the judiciary are called for

The Supreme Court is the custodian of India's 'living' Constitution and the final arbiter of the laws of the land. Though one of the three equal pillars of the State, it holds an exalted position not only by constitutional design, but also in the public conscience, earned through its untiring efforts in upholding the Constitution and steadfast protection of citizens' rights.All citizens, including these authors, repose high expectations on the SC as it discharges its dharma of justice.It is the final authority in ensuring closure to disputes. Though it may not necessarily always be right (due to human frailties), it is always final—and the institution has lived up to this expectation umpteen times. However, certain recent developments suggest that this finality is no longer assured. Judgements are being revisited, stayed, recalled, or altered—creating a perception that a matter is not truly settled even after the SC has pronounced its verdict.This blurring of finality raises important questions on the certainty of law, the authority of judicial outcomes, and the stability of legal systems.Consider a few recent examples that happened in quick succession. The resolution plan of Bhushan Power and Steel was rejected in May while disposing of an appeal filed five years ago. At end July, a bench headed by the Chief Justice of India recalled the judgement for review, as it had not correctly considered the legal position laid down by a catena of judgements.

Another order in early August, while castigating a high court judge for lack of knowledge in criminal laws, de-rostered him from hearing criminal cases. On a request from the Chief Justice of India, the same bench deleted some of the directions from the judgement.A third instance is the mid-August stay of the order given few days earlier on the stray dog problem in the national capital. The review order issued by a different three-judge bench modified and mollified some of the directions in the order impugned. All these reversals, stays or reviews followed massive public and expert outcries on the original orders. Even arbitral awards, which by design are final and not generally appealable, are not immune to uncertainty. In DMRC vs Delhi Airport Metro Express, the award traversed the SC through a special leave petition, a review petition, and a curative petition, with the court eventually overturning its own earlier decision.

The need for revisiting orders by the Supreme Court, especially within a short span of time, is a very serious matter irrespective of whether public sentiment or its own conscience is the reason. It undermines the very foundation of finality and precedents provided under Articles 141 and 137 of the Constitution.To stand by things decided—stare decisis—is an age-old principle followed by all established judicial systems. A weakening of this principle, that too in the face of several other constraints, accentuates the limitations of the judiciary in dealing with the mounting pendency and the trauma of the affected parties waiting for justice.Let's make it abundantly clear that we are not on the merit of any of these judicial pronouncements, only on about the processes that make certainty a casualty. Even in major commercial matters where uncertainty can have larger economy-wide or international ramifications, incurring huge opportunity costs.

The SC handles an astounding number and variety of cases, ranging from fundamental constitutional questions, human rights, diverse PILs, to matters of daily life—health, pregnancy, property, agency inaction/hyper-action, municipal failures like on street animals, socio-cultural disputes, and even individual instances of cheating, pre-arrest bails, etc. After all, India is a litigants' paradise.

Managing such a vast and complex docket inevitably takes an enormous toll on the learned judges and the system.The high pendency of cases at every stage of the judicial hierarchy is well known. Delays are often attributed to lingering vacancies, inadequate number of judges, support staff, infrastructural constraints, and even the executive-judiciary tussle on overreach. These issues have existed for long, aggravating the cold reality of justice being denied through delays. But 'delayed-then-hurried' orders are also hurting finality, aggravating the problem of pendency.

The rising number of revision, review, and curative petitions is clear evidence of the malady affecting certainty like a double-edged weapon.Given these issues, the SC should suo motu take up the mandate of structural reforms from within. It should address issues like limiting the number of appeals, revision, and review, and reimagining the role of high courts as constitutional courts.It can also ensure a high degree of professionalism in minimising adjournments, weeding out frivolous petitions, writing matter-of-fact orders, and revisiting the selection and confirmation criteria for judges.The higher judiciary can implement many of the internal reforms under Articles 145 and 225. Reforms needing support from the other two pillars of the State should be in response to an agenda set by the judiciary.Proactive judicial reforms by the executive or legislature may be seen as interference. Therefore, in parallel to demanding executive action on funding, appointments, and other administrative steps, the SC must lead a structural and procedural transformation from within. That should guarantee fast finality to disputes and in ensuring 'complete justice' to the people.

Sensex, Nifty trade flat after opening lower amid F&O expiry, US visa curbs

NEW DELHI. (Agency)

Benchmark stock market indices opened on a cautious note on Thursday, weighed down by persistent foreign outflows, US visa curbs and the expiry of monthly derivatives contracts. After slipping in early trade, both indices clawed back gains.

At 9:28 am, the S&P BSE Sensex was up 95.55 points at 81,811.18, while the NSE Nifty50 rose 25.65 points to 25,082.55. Broader market indices also traded in the green, though overall sentiment on Dalal Street remained mixed.Some of the top gainers on the Nifty50 were BEL, Hindalco, ONGC, Apollo Hospitals and Adani Enterprises. On the other hand, the top losers were Tata Motors, Titan, Asian Paints, Maruti and SBI Life.Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist at Geojit Financial Services, noted that the lack of fresh triggers has kept the market in a drifting phase. "Auto stocks have been bullish, partly discounting the potential earnings growth of the industry. The significant drag on the market throughout this year has been the sustained selling by FIIs. The FII strategy of selling in India and buying in other markets has paid rich dividends as evidenced by the huge underperformance of the Indian market vis--vis others," he said.

He highlighted the stark contrast: while the Nifty is down 3.6 percent year-on-year, Hong Kong's Hang Seng index is up 38.6% and South Korea's Kospi has surged 33.73%."This huge underperformance and the high valuations in India has emboldened FIIs to continue selling. The reforms being implemented in India along with the low interest rate regime have the potential to push economic and corporate earnings growth higher, which should bring FIIs back. But we don't know when this will happen on a sustained basis. This is the right time for investors to continue accumulating high-quality stocks. Patience is the key," he added.

Housing sales drop 9% year-on-year in top 7 cities in July–September quarter: Anarock

NEW DELHI.(Agency)

Housing sales in India is likely to have fallen 9% year-on-year in the July-September quarter of calendar year 2025 (Q3 2025). According to Anarock data, approximately 97,080 units were sold across the top 7 cities in Q3 2025, against 1.07+ lakh units in Q3 2024. Despite lower overall sales volume, total sales value in the period went up by 14% - from Rs 1.33 lakh crore in Q3 2024 to Rs 1.52 lakh crore in Q3 2025.

Anarock stated that despite the monsoons and the perceived inauspicious 'shraad' period, housing sales in Q3 rose 1% quarter-on-quarter in Q3. Overall, the housing market is so far reasonably steady in 2025, with expectations for a festive boost ahead for which developers have several projects lined up, it added. Anuj Puri, Chairman of ANAROCK Group, said that the impact, if any, of the new H1-B visa norms announced by the US on Indian residential market bears close monitoring.

"While housing affordability remains a challenge across cities for many buyers, price growth has tapered down moderately compared to the previous few years, when we saw double-digit yearly growth in the top 7 cities," added Puri.After staggering year-on-year average price growth in the last three years, the top 7 cities saw average price growth of 9% annually - from Rs 8,390/sq. ft. in Q3 2024 to Rs 9,105/sq. ft. in Q3 2025. Among the top 7 cities, NCR saw the highest 24% annual jump in average prices. On a quarterly basis, average prices in the top 7 cities rose by 1%, as per Anarock data.

Mumbai Metropolitan Region (MMR) recorded the highest sales among the top 7 cities in Q3 2025, with approx. 30,260 units sold - a quarterly decrease of 3 percent and a 16 percent yearly drop. Pune saw approx. 16,620 units sold in Q3 2025, a decrease of 13 percent y-o-y.

Airbus Board's meeting in India: $2bn sourcing target, key partnerships on agenda

New Delhi.(Agency)

Aircraft maker Airbus will hold the meeting of its board of directors in the national capital early next week, according to an official. This will be the first time that the Airbus board will be meeting in India, a key market for the aerospace major, which already sources more than USD 1.4 billion worth of services and components from the country.An Airbus spokesperson on Thursday said the company sees great potential in India's talent pool, its thriving industrial ecosystem and its clear 'Make in India' vision.Airbus, which has a significant presence in India's civil aviation and defence segments, is also setting up two Final Assembly Lines for the H125 helicopters as well as the C295 military aircraft. Both FALs are being set up with Tata Advanced Systems Ltd.The board of directors of Airbus will be meeting in the national capital early next week, and it will be the first time that the board meeting will be taking place in India since the aircraft maker started operations here six decades ago, the official said.

There are 12 members on the board, chaired by René Obermann, as per the Airbus website. The Airbus spokesperson said the board of directors' visit to India is a significant moment and that the country is a critical hub for its global operations."We have already crossed the milestone of sourcing over USD 1.4 billion in components and services annually. We are on track to significantly increase that figure, as we continue to further integrate India into our global value chain," the spokesperson said in a statement.

India to establish nuclear liability fund to attract global suppliers

A dedicated nuclear fund is a major shift in the current risk-sharing rules.

CHENNAI. (Agency)

The Indian government is preparing to set up a dedicated nuclear liability fund that will cover compensation claims exceeding ?1,500 crore ($169 million) in the event of a nuclear accident.The initiative is designed to address long-standing concerns over risk-sharing, which have discouraged global suppliers and private firms from investing in India's nuclear energy programme, Reuters reported on Thursday quoting two senior government officials familiar with the development.A dedicated nuclear fund is a major shift in the current risk-sharing rules. At present, India's nuclear liability law makes plant operators responsible for damages up to Rs 1,500 crore, with the

government assuming responsibility for any claims beyond that threshold. However, the absence of a clear financial framework for liabilities above this limit has created uncertainty, particularly for foreign equipment makers wary of open-ended risks.The new fund would create a structured pool of money—backed by government allocations and potentially supported by industry contributions—to meet compensation requirements in excess of the operator's liability cap. Officials said the plan aims to provide "predictability and confidence" for suppliers, while ensuring victims of a nuclear accident have a guaranteed source of relief.Industry analysts note that liability concerns have been a major stumbling block in India's nuclear sector. Despite ambitious goals to expand nuclear capacity as part of its clean energy transition, India has seen limited foreign participation, especially from US, French and Japanese suppliers, who have sought stronger safeguards against financial exposure.By introducing a dedicated fund, the government hopes to reassure these players and accelerate stalled projects. "This mechanism could open the door for advanced reactor technologies and greater private involvement in construction and supply chains," says an industry expert quoted in the report.

Why is it important

Nuclear power accounts for less than 3 percent of India's total electricity generation, but the government wants to significantly scale up capacity to reduce reliance on fossil fuels. A more secure liability framework is seen as critical to achieving these targets, particularly as India works toward its 2070 net-zero emissions goal.The proposed fund is expected to be finalised in consultation with regulators, state-owned operators such as NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Ltd.), and global suppliers. Formal details, including the size of the corpus and its funding model, are likely to be announced in the coming months, according to the officials quoted in the Reuters report.

Gold slips from record high. 3 factors explained

Gold retreated from its record peak this week, leaving investors curious about what triggered the fall. Here are three key factors behind the dip.

New Delhi.(Agency)

Gold retreated from record peaks on Thursday, with 22-carat and 24-carat gold showing declines. A firmer US dollar and cautious trading ahead of upcoming economic data contributed to the drop.

STRONGER DOLLAR PUTS PRESSURE

One big reason for the dip was a firmer US dollar, which gained about 0.6%. Since gold is priced in dollars, a stronger greenback makes it more expensive for buyers holding other currencies. US Treasury yields also inched higher, adding further weight.

FED SIGNALS AND MARKET CAUTION

Traders were also cautious after Federal Reserve Chair Jerome Powell spoke on Tuesday. He avoided giving clear signals on the timing of future interest rate cuts, stressing the need to balance inflation risks with a slowing job

market.Markets still expect two small rate cuts later this year — one likely in October and another in December, according to the CME FedWatch tool. Lower interest rates usually favour gold, as it does not offer interest but gains appeal when yields fall.

ALL EYES ON KEY US DATA

Attention now turns to US economic numbers due later this week. Investors are waiting for jobless claims data on Thursday and the Personal Consumption Expenditures (PCE) index on Friday, which is the Fed's preferred inflation gauge. These updates could give fresh clues on where interest rates are headed.Additionally, geopolitics also remains in focus. Ukraine said it had struck two oil pumping stations in Russia's Volgograd region overnight, keeping tensions high. Such developments often increase the appeal of safe-haven assets like gold.Simply put, gold's retreat shows how sensitive the metal is to moves in the dollar, interest rate expectations, and geopolitical risks. While prices eased from record highs, many traders remain watchful of upcoming US data and global tensions that could quickly swing momentum again.

Missed the ITR deadline You will now have to file under new tax regime

New Delhi.(Agency)

Filing your income tax return (ITR) on time is more than just ticking a box—it can affect how much tax you pay and which regime you can choose. Yet, many taxpayers wait until the last minute, risking not only late fees but also losing the flexibility to stick with their preferred tax regime.The Income Tax Department says, "It is emphasised that the choice of old tax regime can be made only before the due date of filing the return u/s 139(1) of I T Act."CA (Dr) Suresh Surana echoes this point, "Taxpayers who miss the due date for filing their ITR cannot later opt for the old tax regime. The choice is available only when the return is filed on time."

OLD VS NEW REGIME: WHAT YOU NEED TO KNOW

The new tax regime is now the default. It offers lower tax rates but comes with fewer exemptions and deductions. Taxpayers can still opt for the old regime, but only if they file their returns by the due date.This year, for instance, those who missed the September 16 deadline for AY 2024-25 and had opted for the old regime to claim exemptions will now have to file belated returns under the new regime.

Suresh Surana adds, "In simple terms, if you fail to file your ITR by the deadline and had chosen the old tax regime, you will have no option but to file under the new regime."For taxpayers with business or professional income, the rules are stricter. Filing Form 10-IEA on or before the deadline is mandatory to continue under the old regime. Missing this step automatically shifts you to the new regime for that year.

WHY LATE FILERS ARE RESTRICTED TO THE NEW REGIME

The Income Tax Department aims to simplify administration and reduce misuse of extended timelines. The new regime, with fewer deductions and simpler compliance, makes processing easier and encourages timely filing.

Suresh Surana explains, "By mandating that the old regime can be chosen only when the return is filed within the original due date, the Department ensures certainty, timely compliance, and reduces last-minute adjustments."

THE COST OF FILING LATE

Filing your income tax return late can be costly, no matter which regime you are under. A late fee of up to Rs 5,000 may be levied, though it is capped at Rs 1,000 for incomes below Rs 5 lakh.In addition, interest accrues at 1% per month on any unpaid tax. Taxpayers may also lose certain deductions and the ability to carry forward losses. In cases of concealment or misreporting, penalties can reach 50% of the tax avoided. In serious instances, prosecution is possible, with imprisonment ranging from three months to seven years, along with a fine, says Surana.

Zoho Corp: Indian software suite that aspires to rival Google and Microsoft

Kolkata.(Agency)

Ashwini Vaishnaw, one of the most technically accomplished members of the Union cabinet, has recently posted written on social media that he is switching to Zoho, an Indian platform which allows one to prepare documents, spreadsheets & presentations — something without which modern executives and businesses can hardly function even for a day. "I am moving to Zoho — our own Swadeshi platform for documents, spreadsheets & presentations. ???? I urge all to join PM Shri @narendramodi Ji's call for Swadeshi by adopting indigenous products & services," Ashwini Vaishnaw, who is piloting the ministry of railways wrote on social media.

But that seems to pit this not-too-well-known platform directly against Google and Microsoft that holds aloft the flag of US tech and claims a near monopoly status — tech Goliaths so to say. What is Zoho? What does it do? Who steers it? Let's have a closer look at this tech David from India.Rooted in Tamil Nadu

Zoho Corporation was set up in 1996, when the Indian economy was breaking the shackles of a controlled economy and was transitioning into a market-oriented one — a startup when the name was not is fashion. Zoho Corporation was

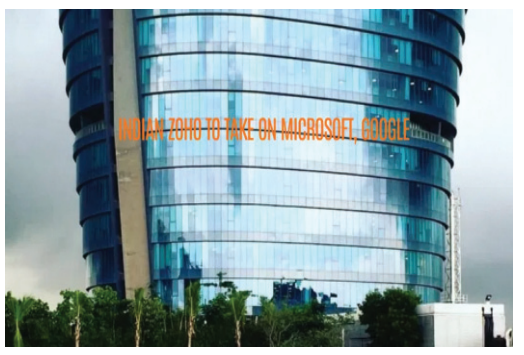

incorporated in the US, but its roots are driven deep in the soil of Tamil Nadu. It is a software-as-a-service (SaaS) company which has its headquarters in Chennai. From top to bottom Zoho smells of "Made in India".

The founders of Zoho

Zoho Corporation was set up by Sridhar Vembu and Tony Thomas, both products of India's rich tech talent pool. Sridhar Vembu graduated from IIT Madras in electrical engineering and went on to receive a doctorate degree from Princeton University. Then he worked as a wireless engineer for Qualcomm in San Diego and San Francisco Bay Area.

Insurance complaints surge 45% in Q2 as health policies drive cases: Report

Rising disputes reveal persistent mis-selling and transparency gaps in India's insurance sector, with policyholders increasingly turning to platforms like Insurance Samadhan to assert rights and seek timely redressal.

New Delhi.(Agency)

India's insurance sector is grappling with a surge in consumer grievances, with Insurance Samadhan – one of the largest private insurance grievance redressal platform in the country — reporting a 45% jump in complaints in the April–June quarter of 2025.The spike indicates both rising policyholder assertiveness and the persistence of structural flaws in how insurance is sold and serviced in India.The company's Q2 2025 Trends Report analysed 4,004 disputes involving claims worth Rs 75.4 crore. Complaints on the platform jumped from 684 in Q1 to 974 in Q2, while the value of contested claims climbed from Rs 83.5 crore to over Rs 119.5 crore, reflecting a growth of 43.10%.The data suggests more customers are bypassing insurer grievance cells and turning to independent platforms to seek redressal.

HEALTH INSURANCE DISPUTES IN FOCUS

Health insurance dominated the complaints landscape, accounting for 67.5% of all disputes. Life insurance followed at 25.5%, while general insurance made up 6.9%.Endowment policies emerged as the most mis-sold category, exposing customers to penalties, reduced returns, and even capital erosion.On a year-on-year basis, complaints linked to mis-selling rose 11.2% compared to Q2 2024, and the value of disputed claims increased by nearly 10%.The demographic profile of complainants points to changing consumer behaviour. The 31–40 age group was the most active in challenging insurers, highlighting how younger policyholders are more willing to push back against unfair practices.

Geographically, Uttar Pradesh accounted for the largest share of grievances at 16 per cent, reflecting growing awareness even outside the metros."It shows that policyholders, especially the younger generations, are willing to stand up for

their rights, knowing there is a platform like Polifyx to rely on. This motivates us to work harder to protect consumer interest and restore faith in the USD 145.80 billion insurance industry," said Shilpa Arora, Co-founder and COO of Insurance Samadhan.The data also underscores how technology is lowering barriers to redressal. Insurance Samadhan's Polifyx app, which allows users to check their policies through a 'Know Your Policy' feature, has simplified grievance filing and made it easier to flag mis-selling.

The company said the growing confidence of policyholders in such tools is driving more complaints to the platform.

The trend comes against the backdrop of rising concern over unfair sales tactics. According to data published by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), mis-selling accounted for 20% of all complaints received against life insurers in 2022–23.Of these, half of the complaints against private insurers involved unfair practices, including deceptive sales pitches designed to push products to meet sales targets.

Since its inception in 2019, Insurance Samadhan has resolved more than 20,000 consumer grievances and recovered claims worth over Rs 220 crore. Its Q2 findings underline both the vulnerabilities faced by policyholders and the potential of grievance redressal platforms to restore balance in an industry critical to financial security.

Delhi High Court questions Priya Kapur's plea to disclose Sunjay Kapur assets in sealed cover

➤The application was filed in the ongoing inheritance dispute involving Karishma Kapoor's children, who are claiming a share in their late father's personal assets.

Agency New Delhi.

The Delhi High Court, on Thursday, adjourned until tomorrow a petition filed by late businessman Sanjay Kapur's wife, Priya Kapur, who has sought permission to file a list of his personal assets and liabilities in a sealed cover.The request was filed as part of the ongoing inheritance dispute involving actor Karisma Kapoor's children, who have claimed a share in their father's personal assets.

Senior advocate Shyel Trehan, representing Priya Kapur, argued that the details of the assets include sensitive financial information, the disclosure of which in the public domain could cause irreparable harm. The plea requested that the documents be filed under confidentiality obligations or, alternatively, that a "Confidentiality Club" be constituted to limit access. "I am willing to show it to all parties, but request it be held as confidential," Trehan said.

The court, however, raised questions on Kapur's request, noting that opposing parties required access to details to respond adequately. "The whole suit cannot be in a sealed cover," the bench observed, while inviting suggestions to balance confidentiality with the rights of all parties."It may be problematic for the simple reason that as the alleged beneficiary of the estate, they (Karisma Kapoor's children) have a right to question the assets disclosed. So, tomorrow, if they have to verify and go about asking what has happened, if they are bound with this confidentiality club, how will they ever defend their case?" the court asked.

The court also asked Trehan if there was any judgment to support her request. In response, Trehan said she would present some suggestions by tomorrow.The counsel representing Karisma Kapoor's children argued that details regarding the property should largely remain public. They also alleged that, per their information, "banks have been wiped off", leaving nothing in the account.

Senior advocate Amit Sibal, representing Sunjay Kapur's mother and a class 1 heir, stressed that he must have full access to the asset details to independently verify the will. He described restrictions, including a potential non-disclosure agreement, as "somewhat unusual" and sought assurance that the order would not impede his rights.Another application listed on Wednesday was filed by Rani Kapur, seeking directions to be provided a copy of the Will dated March 21, 2025.After hearing arguments, the court adjourned both matters to the following day to allow counsels to propose a method to maintain confidentiality without infringing on the rights of any party.

Can even a scratch by a dog or cat cause rabies? Here's what doctors say

Agency New Delhi.

When police inspector Vanraj Manjaria—an animal lover who even preserved the ashes of his pets—died recently, it was a dog that was behind his death from rabies. For Manjaria, death came from the scratch of not a street dog, but a pet dog of a family friend he met at a farmhouse he visited earlier this month. His death has sparked several questions about dogs and rabies. But the key question—can just scratch, not bite, cause rabies? And if yes, how does the virus reach the canine's paw?

Manjaria suddenly fell sick on September 15, but by the time he was admitted to hospital in Ahmedabad, it was too late. Doctors told his family he had contracted rabies—a virus with no cure and certain death.None of Manjaria's relatives knew of any bite, and he himself had never mentioned one. Only in the hospital were two scratch marks from a dog's paw discovered on his feet.It has raised the question—can a dog's, or even a cat's scratch, really cause rabies? Here is what doctors have to say.

YES, EVEN A SCRATCH FROM A DOG OR CAT CAN CAUSE RABIES

"It is possible. If the animal is infected with the virus and licks its paws before scratching a person, transmission can occur, though the probability is low," explained Mumbai-based veterinarian Dr Brijesh Raj.

In Manjaria's case, a family relative told India Today Digital that it remained unclear whether the dog that scratched him was alive or not. Generally, after an incident of an animal's bite or scratch, doctors and veterinarians suggest that a close eye on the animal be kept. If an animal is infected by the rabies virus, they usually die within two weeks.

In a first, India test-fires Agni-P missile from rail-based mobile launcher

Agency New Delhi.

India has successfully test-fired its new generation nuclear-capable ballistic missile, Agni-P, off the coast of Odisha. The Defence Research and Development Organisation (DRDO) conducted the test from Dr APJ Abdul Kalam island, showcasing the missile's advanced capabilities.Congratulating Defence Research Development Organisation (DRDO), Union Defence Minister Rajnath Singh pointed out that the intermediate ballistic missile could be launched within a short reaction time from a Rail based Mobile launcher system.

"The first-of-its-kind launch carried out from specially designed Rail based Mobile Launcher, has the capability to move on Rail network without any pre-conditions that allows User to have a cross country mobility and launch within a short reaction time with reduced visibility," Defence Minister Rajnath Singh tweeted.

The Agni-P missile boasts several key features that make it a significant addition to India's defence arsenal.The missile uses a ring laser gyro-based inertial navigation system (INS) and a micro inertial navigation system (MINS), with optional GPS and NaVIC satellite navigation.

The missile's canisterised design allows for easy transportation and storage, reducing the time required for launch preparations.The Agni-P missile has demonstrated high accuracy in its previous tests, making it a reliable deterrent against potential threats.

The successful test-firing of the Agni-P missile has significant implications for India's defence capabilities. It demonstrates India's ability to develop and deploy advanced missile systems, enhancing its deterrence capabilities against potential threats.In the last few weeks, India has successfully tested three advanced missile systems as part of its broader strategic development program.Prior to the Agni P missile test, India had successfully test-fired the Agni-5 intermediate-range ballistic missile on August 20, with a range of up to 5,000 km. The Defence Ministry said the launch from the Integrated Test Range in Odisha's Chandipur validated all operational and technical parameters.

When Hindu woman marries, her 'gotra' changes: Supreme Court in succession case

Agency New Delhi.

The Supreme Court remarked that the property of a Hindu woman dying without a will and leaving behind no husband and children goes to her husband's heirs and not to her family as her "gotra" changes when she marries under the Hindu law.

These remarks came on Wednesday while the top court was hearing a plea challenging Section 15(1)(b) of the Hindu Succession Act, 1956, which provides that when a Hindu woman dies intestate, her property passes to her husband's heirs if she leaves no husband or children.During the proceedings, the bench led by Justice BV Nagarathna reminded petitioners to consider the cultural framework underlying the law.

"Before you argue, please remember. This is Hindu Succession Act. What's the meaning of Hindu, how is Hindu society regulated, what's the meaning? Though you may not like to use all those words...but 'kanyadan', when a woman is married, her gotra is changed, her name is changed. She can seek maintainance from her husband...," the bench noted.

Justice Nagarathna pointed out ritual practices in southern India, stating, "In southern marriages, there is even a ritualistic announcement that she is moving from one gotra to another. You cannot wish away all of this."

The bench said that once a woman is married, her responsibility under the law rests with her husband and his family."She will not seek maintenance from her parents or siblings. If a woman is married, who is responsible under the act? Husband, in-laws, children, husband's family. She will not file a maintenance petition against her brother! It's against husband, his estate... If a woman does not have children, she can always make a will," Justice Nagarathna added.

Poll body mandates postal ballot to be counted before final EVM round

Agency New Delhi.

The Election Commission of India (ECI) has introduced changes to the vote count process, mandating the completion of postal ballots before the final round of counting of votes cast via Electronic Voting Machines (EVM) begin at centres.Normally, counting of postal ballots begins at 8 am and EVM counting half an hour later.According to the previous rules, EVM counting could, in theory, proceed independently of postal ballot counting, and there remains a possibility that it may conclude before the postal ballots are fully tallied.Counting of postal ballots generally gets completed before the counting of EVM votes.In a bid to ensure uniformity and absolute clarity in the counting process, the ECI has decided that the final or second-last round of EVM counting will be taken up only after the counting of postal ballots is fully completed at the respective counting centres.

The vote-counting changes come with just a few months left for the Bihar Assembly elections.

As the high-stakes polls are fast approaching, the Congress has ramped up its attack on the ECI and the Centre over the "vote theft" issue and special intensive revision of the electoral rolls in Bihar.Last week, Congress MP Rahul Gandhi doubled down on his claim that the poll body was "protecting vote chors", or thieves.

"Wake up at 4 am, delete 2 voters in 36 seconds, then go back to sleep – that's how vote theft happened! The watchdog of elections stayed awake, kept watching the theft, and kept protecting the thieves," he tweeted on September 19.In response, the Election Commission has rubbished the Congress MP's claims, asserting that no voters could be deleted online by the public.

UP man dies by suicide after neighbours' false molestation case, leaves 6-page note

Agency New Delhi.

A bakery owner in Lucknow died by suicide after being falsely implicated in a molestation case filed by his neighbours following a long-standing dispute over the construction of a ramp. Virendra Yadav left a six-page suicide note and his family believe that he took the extreme step over fear of social stigma emanating from the false case, as well as concerns over his daughter's marriage.Yadav, who ran the bakery in the city's Manak Nagar area, had a dispute with his neighbours, Surjeet Yadav and his wife, Anita, over constructing the ramp outside their house.As the dispute escalated, the matter reached court. The neighbours, however, continued the construction despite a court order to halt it.

When Virendra protested, the couple filed a false molestation case against him and his entire family.According to Virendra's wife, Neelam, he was deeply distressed after receiving the summons for the false case. He feared that he and his family would lose their respect in society and would also lead to implications for his daughter's marriage.He felt that if he went to jail, no one would marry his daughter. Burdened by this humiliation and fear, he took his own life by consuming poison. In his suicide note, he extensively described the ordeal and torment he faced from his nighbours.

The victim's son, Abhay, claimed that the police filed the false case without any evidence, despite the presence of cameras installed all around their house.Abhay stated that a relative of the accused couple is in the Special Task Force (STF), and under pressure from him, the police acted unilaterally.

He also alleged that when he sought help, the police instead supported the accused. Even after Virendra's death, the police spent the entire day preparing the inquest report, forcing the family to perform the last rites at night.Virendra Yadav and his family weren't the only ones who were being harassed by Surjeet and Anita Yadav.

L&T, BEL forge strategic alliance to power India's 5th-gen fighter jet programme

Agency New Delhi.

TLarsen & Toubro (L&T) and Bharat Electronics Limited (BEL) have announced a strategic partnership to jointly support the Indian Air Force's Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) programme. The two defence technology leaders will form a consortium to respond to the Expression of Interest (EoI) issued by the Government of India's Aeronautical Development Agency in the coming weeks.The collaboration aims to contribute significantly to India's fifth-generation fighter aircraft initiative by combining L&T's expertise in developing strategic defence and aerospace platforms with BEL's proficiency in defence electronics and systems. The partnership aligns with the Government of India's vision for an 'Atmanirbhar Bharat' and represents a major milestone in enhancing the country's indigenous defence manufacturing capabilities.

L&T and BEL have previously played instrumental roles in India's Light Combat Aircraft (LCA) programme, supplying critical aero-structure modules and developing mission-essential avionics and electronic systems. Building on this legacy, the consortium seeks to deliver high-quality, next-generation technologies tailored to the requirements of the Indian Air Force.Commenting on the development, S N Subrahmanyan, Chairman & Managing Director, L&T, stated, "The collaboration with BEL marks a significant leap in our commitment to the modernisation of India's defence capabilities. We are honoured to be working with BEL to deliver next-generation technologies for the Indian Air Force. Both the organisations are leaders in our respective domains and our combined efforts will play a crucial role in bolstering national security and advancing self-reliance.

"Protesting A Right But...": Ladakh Lt Governor's Warning Over Deaths

Agency New Delhi.

The violent statehood movement protests in Ladakh 24 hours ago - in which four people were killed - were the result of a "conspiracy", Lieutenant Governor Kavinder Gupta told Thursday afternoon, as he also expressed sorrow over the incident and the deaths.

The Lt Governor did not name the alleged conspirators but referred darkly to 'comparisons' with the violence in Bangladesh last year (where a student-led protest overthrew the Sheikh Hasina government) and in Nepal this month (a 'Gen Z' agitation forced a change in government)."In a democratic system, protesting is a right. But it must be done in a peaceful manner. For the past two days, attempts have been made to incite the people of Ladakh... and the protest held here was compared to those held in Bangladesh and Nepal. This smells of a conspiracy."

"Then it becomes clear... somewhere there are 'foreign powers' involved," he said, "... gradually many things will become clear. Who is making this happen? Why was this day chosen?"The Lt Governor pointed out that the Ladakhi people had welcomed the formation of the Union Territory of Ladakh in 2019, after the federal government scrapped special status for Jammu and Kashmir and split the state into two UTs. "Ok... everyone has the right to say what they want (referring to the protesters). But Ladakh will not be allowed to become a place of violence."

"Ladakh is a peaceful, religious. and devout environment. Some people (again, referring to the 'conspirators') will come here and do this. No matter how big a person is, there will be action."

The comments come after Ladakhi activist Sonam Wangchuk was blamed for the violence."In spite of many leaders urging to call off the hunger strike, he continued... and misled the people through provocative mentions of Arab Spring-style protest and references to Gen Z protests in Nepal," the Home Ministry said in a statement.

On Wednesday the Lt Governor issued a curfew and blamed the protesters for the violence, which included a Bharatiya Janata Party office being vandalised and a CRPF, or Central Reserve Police Force, vehicle set on fire. "Those who instigated protests are responsible for the deaths."

He also said a mob 'tried to burn CRPF men inside the vehicle'.The government said 30 police and CRPF personnel were injured in the violence.

The local leaders, however, have alleged use of disproportionate force by security forces.

The violence has also sparked a political row, with the BJP accusing a Congress Councillor, Phuntsog Stanzin Tsepag, who has been charged in connection with the clashes. However, Mr Wangchuk pointed out the Congress cannot muster 5,000 young Ladakhi men and women to a protest.

Meanwhile, the police have launched a major crackdown and arrested 50 people for the violence. It is unclear, though, if the Congress Councilor was one of those arrested.Over the past three years, Ladakh has seen growing unrest against direct federal rule.

NEWS BOX

Indonesia's $10 Billion Free Meals Plan In Turmoil As Over 1,000 Students Fall Ill

World. (Agency)

More than 1,000 children in Indonesia's West Java have suffered food poisoning this week from school lunches, authorities said, the latest in a series of outbreaks and another setback for the president's multi-billion-dollar free meals programme.

The mass poisoning was reported in four areas of West Java province, its Governor Dedi Mulyadi told Reuters on Thursday, which came as non-governmental organisations issued calls to suspend the programme due to health concerns.

The latest cases follow the poisoning of 800 students who ate school lunches last week in West Java and Central Sulawesi provinces, which were supplied under President Prabowo Subianto's signature free nutritious meals programme.

Questions have been raised about standards and oversight of the scheme, which has expanded rapidly to reach over 20 million recipients, with an ambitious goal of feeding 83 million of Indonesia's 280 million people by year-end. The programme's 171 trillion rupiah ($10.22 billion) budget will double next year.

Governor Mulyadi said more than 470 students fell sick in West Bandung on Monday after eating the free lunches and three more outbreaks took place there on Wednesday and in the Sukabumi region, affecting at least 580 children.

"We must evaluate those running the programme... And the most important thing is how to deal with the students' trauma after eating the food," Mulyadi said, adding that small hospitals in West Bandung were overwhelmed by sick students.

Prabowo's office did not immediately respond to a request for comment on the latest cases. Dadan Hindayana, head of The National Nutrition Agency that oversees the free meals programme, said kitchens with poisoning cases had been suspended.

2 Indians Sanctioned By US For Selling Fake Pills Filled With Fentanyl

Washington.(Agency) :

The United States has sanctioned two Indian nations over accusations of running online pharmacies that sold fake prescription pills filled with deadly drugs like fentanyl and methamphetamine to American consumers. The US Department of the Treasury said Sadiq Abbas Habib Sayyed (39) and Khizar Mohammad Iqbal Shaikh (34) collectively supplied "hundreds of thousands of counterfeit prescription pills filled with fentanyl and other illicit drugs" to victims across the United States.

Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) also designated one India-based online pharmacy-- KS International Traders (a.k.a. "KS Pharmacy")-- for its role in these criminal operations. The pharmacy is owned by Shaikh.

What US Authorities SaidAccording to a statement issued by US authorities, based in India, Sayyed and Shaikh worked with Dominican Republic and US-based narcotics traffickers to sell counterfeit pills. They used encrypted messaging platforms to market and sell these pills as discounted, legitimate pharmaceutical products, which were instead filled with illicit drugs like fentanyl, a fentanyl analogue, and methamphetamine.Sayyed and Shaikh were previously indicted in September 2024 on narcotics-related charges by a federal grand jury sitting in the Southern District of New York. Even after being exposed for his criminal activity in in DOJ's 2024 indictment, Shaikh continues to operate KS International Traders, the authorities said.Under US sanctions, all property or assets the two men hold in the US have been frozen. Moreover, all American businesses or individuals have also been barred from engaging with them. Violations of the order carry the risk of civil and criminal penalties.

Banned XL Bully Kept As Pet Dy UK Family Kills 10-Year-Old Daughter

World.(Agency)

A 10-year-old girl named Savannah Bentham tragically died after being attacked by her family's pet XL Bully dog at their home in East Heslerton, North Yorkshire, according to The Metro.

The incident took place in November last year when Savannah was left alone watching television with the six-year-old dog, named Biggie. Her mother had briefly left their static caravan to get help fixing a gas canister connection. Her father was at work at the time.When her mother returned, she found Savannah on the floor with serious injuries and the dog covered in blood. Emergency services were called immediately, and bystanders tried to help, but sadly, Savannah died at the scene from injuries to her neck, as per the news portal.

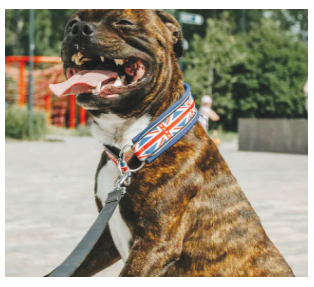

An inquest into her death was held recently. According to Detective Chief Inspector Matthew Wilkinson, there had been no previous signs of aggression from the dog, and it was described as a calm and lazy pet.

Although XL Bully dogs are banned under UK dangerous dog laws, the family had legally kept Biggie under exemption rules. They had met all legal requirements, including registering the dog, neutering it, microchipping it, and ensuring it wore a muzzle in public.Despite these precautions, the dog fatally attacked Savannah. There were no witnesses, and the dog was later put down. A post-mortem examination of the dog showed no health issues or physical conditions that might have caused sudden aggression.North Yorkshire's senior coroner, Jon Heath, concluded that Savannah died as a result of injuries caused by the family dog.

Many leaders back a UN call to address challenges together but Trump says 'America First'

UNITED NATIONS. (Agency)

From France to South Korea, South Africa to Suriname, leaders gave strong support Tuesday to the UN chief's call to work together to address global challenges – war, poverty and climate chaos. But US President Donald Trump had other ideas and touted his "America First" agenda.

UN Secretary-General Antonio Guterres opened the annual meeting of presidents, prime ministers and monarchs at the General Assembly with a plea to choose peace over war, law over lawlessness, and a future where nations come together rather than scramble for self-interests.

France's President Emmanuel Macron warned that 80 years after the UN was founded on the ashes of World War II, "we're isolating ourselves.""There's more and more divisions, and that's plagued the global order," he said. "The world is breaking down, and that's halting our collective capacity to resolve the major conflicts of our time and stopping us from addressing global challenges."

But Macron said a complex world isn't reason "to throw in the towel" on supporting the UN's key principles of peace, justice, human rights and nations working together.Only respectful relations and cooperation among peers make it possible to fight against military proliferation, address climate change and have "a successful digital transformation," he said.A call for collaboration

Speaker after speaker made similar appeals to support multilateralism.Suriname's President Jennifer Geerlings-Simons called multilateralism "one of humanity's most important achievements, which needs our protection at this time of change."South Africa's President Cyril Ramaphosa said "our collective membership of the United Nations is our shared humanity in action," and the UN at 80 compels members to build "an organization that is able to address our common challenges."As South Korea's President Lee Jae Myung put it, "The more difficult the times are, the more we must return to the basic spirit of the UN." He added, "We today must cooperate more, trust more, and join hands more firmly, in order to build a better future, a better world

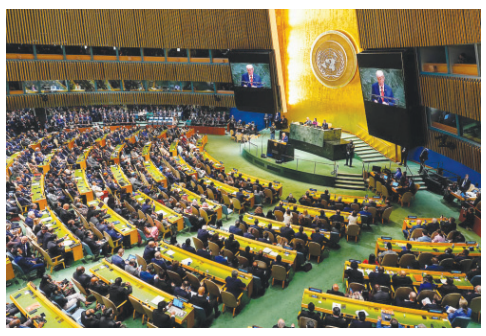

for future generations."The General Assembly meeting continues Wednesday with the leaders of Ukraine, Iran and Syria among the speakers.Guterres in his remarks noted the world is becoming increasingly multipolar — certainly a nod to rising economic powers China and India but a slap to the US insistence on superpower status.The UN chief said a world of many powers can be more diverse and dynamic, but warned that without international cooperation and effective global institutions there can be "chaos."But Trump, making the first address to the General Assembly since he was elected to a second term last November, ceded no ground and gave an "America First" speech.The United States has the strongest borders, military, friendships "and the strongest spirit of any nation on the face of the earth," he boasted. "This is indeed the golden age of America."He portrayed the United Nations as ineffectual and "not even coming close to living up" to its potential, blaming the organization for an escalator that stopped en route to the assembly chamber and for a broken teleprompter. The UN cited a safety function for the escalator incident and the White House for the teleprompter.While Trump told the assembly the UN delivers "empty words — and empty words don't solve war," his tone shifted at a later meeting with Guterres. "Our country is behind the United Nations 100%," the president told Guterres at the start of their first meeting since his reelection."I may disagree with it sometimes, but I am so behind it because the potential for peace at this institution is great.

Jimmy Kimmel is back on ABC to big ratings, but some US affiliates still refuse to air his show

NEW YORK.(Agency)

Jimmy Kimmel is back on his ABC late-night show, but it's still a mystery when — or if — viewers in cities such as Washington, Seattle and St. Louis will be able to see him again on their televisions.ABC stations owned by the Nexstar and Sinclair corporations took Kimmel off the air last week on the same day the network suspended him for comments that angered supporters of slain conservative activist Charlie Kirk. Those stations kept him off the air Tuesday, when ABC lifted the suspension. The unusual dispute attracted the attention of US senators, who said they wanted to investigate the relationship between the affiliates and US President Donald Trump's administration.Kimmel returned with no apologies, but in an emotional monologue where he appeared close to tears, the host said that he was not trying to joke about the assassination. He also paid tribute to Kirk's widow.And it got a large audience, with ABC reporting nearly 6.3 million people tuned in to the broadcast alone, despite the blackouts in many cities. As is often the case with late-night hosts' monologues, there was a larger audience online, with more than 15 million people watching Kimmel's opening remarks on YouTube by Wednesday evening.ABC says more than 26 million people watched Kimmel's return on social media, including YouTube. Typically,

he gets about 1.8 million viewers each night on television. The numbers released by ABC do not include viewership from streaming services.A spokesman for Nexstar said Wednesday that Kimmel will continue to be preempted from its stations while the company evaluates his show. Together, the Nexstar and Sinclair groups account for about a quarter of ABC's affiliates, many in smaller cities such as Nashville, Tennessee; Lubbock, Texas; or Topeka, Kansas."We are engaged in productive discussions with executives at the (ABC parent) Walt Disney Co., with a focus on ensuring the program reflects and respects the diverse interests of the communities we serve," Nexstar said.Dispute highlights relationship between networks and local stations

The dispute focused attention on the business relationships between television networks and the local stations that carry their programming. In the past, local stations occasionally balked at airing a network show, but it was usually an individual market or two worried about pushing boundaries in language or sexual content, said Ted Harbert, a former top executive at ABC and CBS.What's different this time is groups that have gobbled up multiple stations acting collectively on content for largely political reasons.

"This is how much the country's political divisions have seeped their way into something that has been, for the last 50 or 75 years, a relatively orderly business.

Indigenous groups criticize Ecuador's $47 billion oil expansion plan in Amazon

world. (Agency)

Colombia: Seven Indigenous groups in Ecuador's Amazon have denounced a government plan to offer dozens of blocks of land for oil exploration, saying it threatens their ancestral lands and violates constitutional protections.The criticism targets a plan from the Ministry of Energy and Mines in August to auction the rights for 49 oil and gas projects worth more than $47 billion.Officials say the "hydrocarbon roadmap" is a strategy to modernize Ecuador's oil industry, attract foreign capital and boost production. Their plan includes contract renegotiations and new licensing rounds that the government says comply with existing legal frameworks.Indigenous groups say 18 of the proposed oil blocks overlap their territories — an area roughly the size of Belgium.Leaders from the Andwa, Shuar, Achuar, Kichwa, Sapara, Shiwiar and Waorani peoples say their communities were not consulted and accuse the government of ignoring court rulings that struck down earlier consultations as unconstitutional."The government is pushing ahead with plans to auction 18 oil blocks in our ancestral territories without free, prior and informed consent. That is a constitutional and international right the state is violating," said Nemo Guiquita, a Waorani leader with the Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon. President Daniel Noboa have alarmed environmentalists and Indigenous leaders who say the country's green reputation is unraveling.

Noboa's administration has moved to scrap Ecuador's independent Environment Ministry. He also suported a law passed by the National Assembly that lets private and foreign entities co-manage conservation zones that critics say weakens protections and threatens Indigenous land rights."There have been protests, lawsuits and companies forced to withdraw in the past, but now they are once again offering up Amazon oil fields," Guiquita said. "We are resisting, and we call on the international community to oppose this expansion and help protect the Amazon and our rights."

Ecuador's Ministry of Energy and Mines did not immediately respond to questions from The Associated Press. The government has maintained that a 2012 consultation remains valid and that the hydrocarbon plan follows existing regulations.

The Noboa government has already opened new licensing rounds. In April 2025, international firms submitted bids for four oil blocks, and the government said it planned further auctions in Amazon and sub-Andean regions in late 2025 and 2026.

"The Amazon is not for sale. We ill deend our territories because we have not been consulted — this is our home," said Nadino Calapucha, a Kichwa leader.

The dispute comes amid a state of emergenc and a national strike over fuel prices, extractive projects and the government's failure to honor a referendum limiting drilling in Yasuní National Park.

Harris faces protesters, condemns Israel's war in Gaza on first night of book tour

NEW YORK.(Agency)

Former Vice President Kamala Harris, forced to confront Israel's war in Gaza on the first night of her book tour, expressed compassion for the Palestinians and condemned President Donald Trump for giving the Israeli government "a blank check."

"What's happening to the Palestinian people is outrageous and it beaks my heart," she told a packed New York City performance center on Wednesday night after being interrupted by the first of four pro-Palestinian protesters. "Donald Trump has given (Israeli Prime Minister Benjamin) Netanyahu a blank check to do whatever he wants."The comments came in the midst of a discussion about her new book, "107 Days," which was released on Tuesday and details the hyperspeed campaign she launched against Trump after Joe Biden dropped ut of the 2024 presidential race.Harris was initially scheduled to make one appearance at the 1,500-person capacity Times Square performance center, but her team added a second show earlier in the evening because of high interestFew issues have divided the nation — and the Democratic Party — more than the war in Israel.More than 65,000 Palestinians have been killed since the start of the war, Gaza's Health Ministry said earlier in the month. The conflict erupted after the Oct. 7, 2023, attack by Hamas.Democratic activists in particular have condemned leaders in both parties for not pushing back harder to stop the bloodshed.Harris on Wednesday referenced her support for New York mayoral candidate Zohran Mamdani, a Democrat who has also spoken out against the war in Gaza. She said the two spoke earlier in the day.She said she told him she's "excited" about his candidacy."You are bringing people in, and you are showing that there are voices that want to be heard, have felt left out and are now a part of what you are doing," she said, referencing the conversation. "And that is so powerful."Outside the venue on Wednesday night, dozens of activists protested on the sidewalk. Inside, the event veered off script several minutes after it began when a protester started shouting from the audience."Your legacy is genocide. The blood of the Palestinians is on your hands," the first one, a man wearing a medical mask.

Drone fired from Yemen hits southern Israeli city of Eilat, Medics say 22 people were wounded

JERUSALEM., (Agency)

A drone fired from Yemen struck the southern Israeli city of Eilat on Wednesday, Israel's military said. Medics said at least 22 people were wounded, two of them seriously. It wasn't immediately clear if they were hurt by the drone or an interceptor.In the Gaza Strip, at least 19 Palestinians were killed by Israeli fire, according to local hospitals.Iran-backed Houthi rebels in Yemen have regularly fired drones and missiles at Israel — and attacked international shipping — in what they say is solidarity with Palestinians in Gaza. The vast majority of the fire directed at Israel has been intercepted or fallen in open areas without wounding anyone.

The Houthis claimed the latest attack, saying in a statement that they had fired two drones at Israel.

Israel has carried out retaliatory airstrikes on Yemen after past attacks. Defense Minister Israel Katz, in a post on X, warned the Houthis that "anyone who harms Israel will be hrmed sevenfold."

The Israeli military said that "interception efforts were made." The Magen David Adom rescue service said that the wounded were taken to a nearby hospital, two of them with "severe shrapnel injuries to their limbs."In Gaza, an Israeli strike hit a group of Palestinians in the built-up Nuseirat refugee camp, killing at least 12 of them, according to the Al-Awda Hospital. Another 18 people were wounded, it said. The Israeli military didn't immediately respond to a request for comment.

Another four people — two children and their parents — were killed in a strike on their home in Nuseirat, according to the Al-Aqsa Martyrs Hospital in the nearby city of Deir al-Balah.Nasser Hospital in southern Gaza said that it received the bodies of three people killed by gunfire while seeking aid. Health officials in Gaza and the U.N. human rights office say hundreds of people have been killed by Israeli fire while seeking humanitarian aid in recent months.The military has said it only fires warning shots when people approach its forces in what it considers a threatening manner.In the Israeli-occupied

West Bank, a 24-year-old was shot and killed by Israeli forces near the northern city of Jenin, according to the Palestinian Health Ministry. The military said they shot and killed a man after he hurled an explosive device at them.The war in Gaza began when Hamas-led militants stormed into Israel on Oct. 7, 2023, killing around 1,200 people and taking 251 hostage. Forty-eight captives are still inside Gaza, around 20 of them believed by Israel to be alive, after most of the rest were freed in ceasefires or other deals.Israel's ongoing retaliatory offensive has killed more than 65,000 people, according to the Gaza Health Ministry. It doesn't say how many were civilians or combatants, but says women and children make up around half the fatalities. The ministry is part of the Hamas-run government. U.N. agencies and many independent experts consider its figures to be the most reliable estimate of wartime casualties.

Israel launched another major ground operation earlier this month in Gaza City, which experts say is experiencing famine. More than 300,000 people have fled, but up to 700,000 are still there, many because they can't afford to relocate.

NEWS BOX

Litton Das to miss Pakistan clash Jaker Ali shares update on Bangladesh captain

ABU DHABI. (Agency)

Jaker Ali Anik provided an update on Bangladesh skipper Litton Das ahead of the crucial Asia Cup Super 4 clash against Pakistan on Thursday, September 25, at the Dubai International Cricket Stadium.

Jaker stepped in for the Tigers against India on Wednesday after Litton failed to recover from a rib injury sustained during a training session earlier on Tuesday.He added that Litton is still undergoing recovery, and Bangladesh will make a final decision on his availability before the Pakistan match.Stay updated on Asia Cup 2025 with India Today! Get match schedules, team squads, live score, and the latest Asia Cup points table.

"He is in recovery. So of course, we will wait

for him until tomorrow's match. As you said, since there is a slight injury, he will definitely try until the very end," Jaker said in the post-match press conference.

'Main focus is batting'

The clash between Bangladesh and Pakistan is effectively a virtual semi-final, with India already assured of a place in the final and Sri Lanka out of contention. After back-to-back wins over Afghanistan and Sri Lanka, Bangladesh faltered with a 41-run defeat to India.Jaker noted that while the Tigers have delivered with the ball, their batting must improve if they are to secure a place in the final."The plan for tomorrow's game will remain the same. Our bowling has been very good, and our batting was also good. We've done well in this tournament," Jaker said.

"So, our main focus has to be on the batting. To win the match, we must bat well. There's no reason to be hopeless about tomorrow's game. What applies to them applies to us too, and we will try to put in that kind of performance and go out there to win," Jaker added.

Game is too fast now to rely on one style, so we had to evolve: Satwik-Chirag

New Delhi. (Agency)

India's top men's doubles shuttlers, Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty, have attributed their resurgence to evolving their game and developing service variations over the past 16 months.The former world number one pair has delivered some breathtaking performances recently, following a period sidelined by injuries and illness over the last year and a half.The duo recently won the bronze medal at the World Championships in Paris and followed up with strong performances, reaching the finals of the Hong Kong Super 500 and China Masters Super 750 tournaments.Currently ranked number seven in the world, the nine-time BWF World Tour winners are hoping to add a tenth title to their collection soon. They credit their

consistent performances to a "side-by-side" strategy they have adopted in recent times."We have tried playing side-by-side more often, especially after service to control the pushes," Chirag, who previously relied more on the front-and-back strategy, told PTI Videos."(Malaysian) coach Tan Kim Her told us that many pairs are doing it, and we too felt it worked well. Once a guy serves, the other splits up at the front court to catch the pushes. It has really worked for us in the last two to three tournaments," he added.The duo has also worked on service variations, with Chirag developing a flat serve that has become his key weapon.

"In the last couple of tournaments, we've served a lot better than in the past year. The game is too fast to rely on one style. You need multiple ways to score points, and that's what we are trying to develop," he said.

The past 16 months have been a test of resilience for the pair, with Satwik battling a shoulder injury and Chirag facing fitness issues. Their ranking dropped to 27 at one stage, raising concerns in the badminton circles.

India's fielding lapses can cost them later: Irfan Pathan warns ahead of Asia Cup Final

India's fielding lapses have raised alarms ahead of the Asia Cup final. Former cricketer Irfan Pathan warns that dropped catches could prove costly, putting pressure on T. Dilip and the team to sharpen their skills.

New Delhi. (Agency)

As India prepares for the Asia Cup final, former cricketer Irfan Pathan has raised concerns over the team's ongoing fielding lapses. While India's squad, led by Suryakumar Yadav, is lauded for having one of the strongest fielding units in the world, their performances in this tournament have shown worrying cracks, particularly in the Super 4 stage against Pakistan and Bangladesh.India secured a spot in the final with a 41-run win over Bangladesh on September 24, but fielding errors were once again a talking point. The team dropped five catches, including four chances off opener Saif Hassan, allowing him to score a threatening 69. On his YouTube channel, Irfan Pathan highlighted how such mistakes could be punished against stronger opponents:"Another concern for Team India, I know the boys work hard in training, and so does the fielding coach, but the team are making a lot of mistakes. You cannot drop this many catches. Even in the last match four chances were dropped. In this game, two catches were dropped in an over, if it was any other team, it would have punished you. You dropped Saif twice, who was set after scoring a 50, any other day, this would come back to bite you," Pathan said.Fielding issues have sparked debate amongst fans, especially regarding the return of T.

Dilip to the squad. He rejoined the setup ahead of the England tour after being released following the Champions Trophy, and some observers have questioned whether bringing him back was the right call. The scrutiny intensified after India's match against Pakistan, where despite a strong opening stand, sloppy fielding dominated post-match discussions.Former India coach Ravi Shastri suggested that the conditions at the Dubai International Stadium could be partly responsible for the fielding struggles. On the other hand, spinner Varun Chakravarthy, who bowled 2/29 against Bangladesh, insisted there was no excuse for the team's mistakes and emphasised the need for sharper fielding ahead of the final:"But, if you ask me, definitely the ring of fire comes in the eyesight. It's a little bit of a disturbance, we have to get acclimatised to it," he said."We can't give excuses at this level. As a team, we have to definitely start taking those catches. We have qualified for the final, and we should be taking all these catches," Varun added.Despite India's batting and bowling firing on all cylinders, fielding remains a weak spot in the T20 setup. The team has so far escaped major consequences in the Asia Cup, but with the final approaching, the pressure is on T. Dilip and the coaching staff to tighten the side's fielding, ensuring the mistakes of the Super 4 stage don't come back to haunt them.

Rohit and Kohli automatic choices for ODIs, but domestic cricket a must: Kris Srikkanth

Kris Srikkanth has said that both Rohit Sharma and Virat Kohli are automatic choices for him in the ODI team. However, the former selector said that the duo needs to play domestic cricket inorder to get rhythm.

MADRID. (Agency)

Former India opener and national selector said that Rohit Sharma and Virat Kohli are automatic choices for him in ODIs but feels that both men should keep their rhythm by playing domestic cricket. Rohit and Kohli have been absent from the field since the end of the IPL and both men have started their preparations for the upcoming Australia tour.Ahead of the series, however, there was a lot of talk about both men heading towards retirement, and some reports suggested that the tour to Australia could be their final outing. The rumours have since been squashed and Srikkanth said that both men are automatic choices for him for the Australia tour.He went on to say that Rohit would be his captain for the series and the duo should continue playing."Rohit Sharma and Virat Kohli are superstars. In my opinion, they will be

automatic choices for the Australia tour. If I was the chairman of selectors, I would make Rohit Sharma as the captain for the Australia ODI series. Now you're saying rumours about their futures. They should be playing."Ajit Agarkar would have had a word with them. The board would have asked them, how are you going to plan for the series," said Srikkanth on his YouTube channel.Tell them to play domestic ODIsSrikkanth said that the board would have told the duo to play domestic cricket and he feels both men will come and do it.

"The chairman and the board will have a word with them and say that ' you guys will have to come and start playing domestic cricket. Because it is good for you and the team. They need match practice and they will come and do it.""Kohli may be practising in England and Rohit might be doing the same at the NCA. They will be preparing for it. The fact that they said they're available and want to play the 2027 World Cup, hoping that they can win it for the team at that time. That's why they're playing. So I will surely give them the chance to play," said Srikkanth.The former selector stated the importance of domestic cricket for both men as they need to get their rhythm back."You should tell them to play domestic cricket in the ODI format. Tell them to play Vijay Hazare Trophy, to get back in the rhythm. They themselves know it. They were two big captains of the current era.""For a person like Kohli, who have done so much for India, I will give extra leverage surely," said Srikkanth.India will play three ODIs from October 19 to 25, with the team expected to be revealed soon.

Knockout fight! Pakistan, Bangladesh battle for another India clash in Asia Cup final

New Delhi. (Agency)

Pakistan and Bangladesh are locked in for a knockout clash in the Super 4s of the Asia Cup 2025, with a spot in the final against India up for grabs. Suryakumar Yadav and his men sealed the spot with a 41-run win over Bangladesh, meaning that the match on Thursday, September 25, just became all the more interesting.Pakistan have had a rollercoaster ride during the Asia Cup 2025, both on and off the field. While the chatter outside the ground has grabbed headlines, the performances in the ground have caught the eye of the public, but for all the wrong reasons. Salman Ali Agha and his men have failed to impress during the tournament, with their performances considered to be far from convincing. Keeping the win against Oman aside, all the other games have seen Pakistan being criticised.The losses to India were

slammed for the lack of effort and meek surrender, while the UAE almost left Pakistan with egg on their faces. But they bounced back against Sri Lanka, despite making it hard on themselves. While the bowling was on point, the batting, especially from the top-order, was lacklustre and they needed Mohammad Nawaz and Hussain Talat to bail them out in the end.

For Bangladesh, it has been a fine tournament, despite their struggles in T20Is over the past few years. They are a team in transition, but have played with a lot of conviction. While they will want to forget the India loss quickly, the fielding and bowling in the death were positives. Saif Hassan has emerged as a star in the last two games.They beat Afghanistan to reach the Super 4s and beat Sri Lanka as well. Against Pakistan, they would take a lot of heart from their 2-1 series win at home in July. Pakistan will need to ensure they're at the top of their game to make it to the final and Bangladesh won't make things easy for them.

BCCI confirms Shreyas Iyer's break from red-ball cricket, names him India A captain

New Delhi. (Agency)

After loads of speculation, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) has officially confirmed that Shreyas Iyer has requested a six-month break from red-ball cricket. The announcement comes just ahead of India's Test squad reveal for the upcoming home series against West Indies. Iyer has also been named captain of the India A side, set to play a two-match unofficial one-day series against Australia A starting September 30.The decision follows Iyer's recurring back issues stemming from a surgery Iyer underwent in the UK in 2023. He had previously managed these challenges during the last Ranji Trophy season by taking short breaks, but sustained involvement in longer-format games was no longer feasible. As a result, Iyer withdrew from India A's second unofficial Test against Australia A in Kanpur, with vice-captain Dhruv Jurel stepping in to lead the side."Mr Shreyas Iyer has informed the

BCCI of his decision to take a six-month break from red-ball cricket. Having undergone back surgery in the UK and managed his recovery well, he has recently experienced recurring back spasms and stiffness while playing the longer format. He wishes to utilise this period to build endurance, body resilience and work on his fitness. In view of his decision, he was not considered for selection for the Irani Cup." the BCCI statement said.Shreyas Iyer had been tipped to return for India's upcoming Test series against the West Indies, especially after Karun Nair, who featured in the Anderson-Tendulkar Trophy against England in July, failed to leave a strong mark. With Iyer stepping away, the selectors now have to rethink and adjust the middle-order combination.For the India A one-day series against Australia A, Shreyas Iyer will captain a side including Prabhsimran Singh (WK), Riyan Parag, Ayush Badoni, Suryansh Shedge, and Vipraj Nigam. Joining the squad for the second and third matches will be Tilak Verma, Abhishek Sharma, Harshit Rana, and Arshdeep Singh, who are available after completing their commitments with the senior team in the Asia Cup.

Attack, attack: Varun Chakravarthy explains his role in India's bowling lineup

MANCHESTER. (Agency)

India spinner Varun Chakravarthy has explained his role in the bowling lineup, saying that he is aiming to attack, even if it means he may concede a few runs at the beginning. Varun has made a sensational comeback to T20Is for the Indian team and finds himself at the top of the ICC rankings.

During India's win over Bangladesh, the spinner went for 13 in his first over before bouncing back and picking up two wickets and ending with figures of 29 for two in his four overs. This could have been way better had the Indian fielders been on their mark during the innings.Stay updated on Asia Cup 2025 with India Today! Get match schedules, team squads, live score, and the latest Asia Cup points table.

STORIES YOU MAY LIKE

Over 2,000 Delhi schools receive Rs 20.20 crore under composite grant

Gurugram founder's reaction to colleague refusing 9pm work call for chores is viral

Bihar train journey video recorded by woman shows ticketless passengers crowding AC-2

Speaking at the post-match press conference, Varun said that his aim in the powerplay is to look for wickets and not change his mantra even if he goes for runs."In the powerplay, the only aimis to look for wickets and it's just looking for that one ball. If it pitches on that right spot and it turns a little bit and the batter can edge it. So I'm just looking for that and, that's my role in the team. Even if I go for little runs, my aim is to keep on attacking and try to look for more wickets," said Varun.

Continuing to be a work in progressVarun is continuing to work on various aspects of his game, shown by his packed schedule this year. After the IPL, the spinner spent time in the Tamil Nadu Premier League. Varun said that after the tournament he got a break, where he practiced a lot and focused on his batting and fielding more."Right after IPL, we had the State Premier League, Tamil Nadu Premier League. So we played that and, after that, I got one week break, which I definitely went and practiced a lot, and yes, I've been working on my batting also. So that has been batting and fielding. So that has been my focus, as of now," said Varun.Varun has four wickets in as many matches and is expected to be in action on September 26 against Sri Lanka in India's final Super 4s game.

Disha Parmar

Has The Sweetest Wish For Husband Rahul Vaidya: 'Glad You Were...'

Love is in the air for Disha Parmar and Rahul Vaidya! One of the most adorable duos of the TV industry, the couple never shies away from expressing their affection for each other on social media. On September 23, Rahul celebrated his birthday and Disha made sure the day was extra special with a heartfelt post for her husband and it is every bit sweet.Taking to Instagram, Disha dropped an adorable series of pictures from the intimate birthday celebrations. In the first slide, she is seen posing alongside the birthday boy, dressed in a stylish white t-shirt and blue jeans. Disha, on the other hand, looked stunning in a red flared maxi dress. An image of the cake also made it to the birthday carousel. The cake had "Limited edition since 1987," written on it.

Alongside the photos, Disha penned a short but super sweet note for Rahul Vaidya. It read, "Happy Birthday baby! Am soo glad you were born! I Loveee Youuu."

Rahul Vaidya and Disha Parmar's Unbreakable Bond

For those who have followed their journey, this sweet birthday wish was just another reminder of their deep bond. From Rahul's proposal on national television during Bigg Boss 14 to their dreamy wedding in 2021, the two have always dished out major couple goals, giving fans a glimpse of their fairytale-like romance.

Rahul Vaidya's First Home In Mumbai

Rahul Vaidya has many reasons to celebrate these days. Just weeks before ringing in his birthday with wife Disha Parmar, the singer bought his first home in Mumbai's Bandra locality. Talking about the milestone, he, in a chat with Hindustan Times, shared, "Disha (Parmar, actor and wife) and I have been looking for our own house for quite some time now. When you plan to buy a house, you wish to tick the maximum boxes. With this house, we both strongly feel ki apna ghar mil gaya."

He added, "For us to have our own house, jisse hum khul ke apna keh sake, is a dream come true. I feel we all work hard, slog to build our own home, and I'm no different. Iss shahar mein apna ghar banaana sabse mushkil baat hain."Rahul Vaidya was last seen in Laughter Chefs 2, where he was paired with Rubina Dilaik. The show aired on Colors TV.

Dhanush, Kriti Sanon's Tere Ishk Mein Teaser To Be Finally Released? Big Scoop Out

After a heart-wrenching love story, Raanjhanaa, Aanand L Rai and Dhanush are all set for yet another film, Tere Ishk Mein, which also stars Kriti Sanon. The movie, which is set to hit the big screen on November 28, 2025, now has a report stating that Bhushan Kumar and Aanand L Rai have already decided the teaser release date of the film.

As per Pinkvilla, a source close to the development has shared, "A musical teaser of Tere Ishk Mein with montages of the film will be launched in the coming week, and screened on the big screen with Kantara: Chapter 1 and Sunny Sanskari Ki Tulsikumari. The idea of this teaser is to take the audience through the chemistry of two leads – Dhanush and Kriti Sanon. The team is confident to grab eyeballs with the hard-hitting yet heartwarming teaser.

"Tere Ishk Mein follows a long theatrical campaign starting with a teaser, leading to songs, and finally the trailer. The makers will also look to make optimum use of the festive period – Dussehra and Diwali – to push their marketing assets," the source further revealed while sharing that the music of ace composer A.R. Rahman will be the highlight of the film.

The source has further shared that the team of Tere Ishk Mein is aiming to target the youth, and while the digital launch of the teaser will happen next week, it will also screen all across from October 2.

About Tere Ishk Mein

Gulshan Kumar, T-Series, and Colour Yellow present Tere Ishk Mein, produced by Aanand L Rai and Himanshu Sharma, and produced by Bhushan Kumar and Krishan Kumar. The film, directed by Aanand L Rai and written by Himanshu Sharma, is an A.R. Rahman musical with lyrics by Irshad Kamil. Starring Dhanush and Kriti Sanon, the film is scheduled to release worldwide in Hindi and Tamil on November 28, 2025.Earlier in July, Kriti announced the wrap of her upcoming film Tere Ishk Mein directed by Aanand L Rai.

Rani Mukerji Calls Winning National Award For Mrs Chatterjee vs Norway 'Deeply Personal' For This Reason

Rani Mukerji received her first National Film Award in the Best Actress category for Mrs. Chatterjee vs Norway (2023), and for her, this win was grand and special because she got a call about winning the award on the day she inaugurated her new office at a place her dad used to live.While talking about her grand win for Mrs Chatterjee vs Norway, Rani Mukerji shared with HT, "It was truly surreal to hear about receiving the award, as I was performing a Griha Pravesh puja for my new office, which is located at the place where my dad used to live. I had my father on my mind the whole day.

I had just finished the puja, and as soon as I sat down, I received the call about the National Award. I truly felt it was my dad's blessing that it happened in such a way that his presence felt really strong. I was missing him deeply that day, especially because I was doing the puja in the very room where he had passed away."

The actress further continued and shared, "Of course, winning it for Mrs. Chatterjee vs Norway makes it even more special because, as I've mentioned in earlier interviews, the character of Devika was someone I had modelled on my own mother. I had my mom in mind throughout the shoot. So, in a way, the character I played, Devika, was very much like her. It feels like both my parents have blessed me with this National Award. It's deeply personal and quite surreal in that sense."

Rani Mukerji's National Award Attire

Rani Mukerji, who won the Best Actress in a Leading Role award for her performance in Mrs Chatterjee vs Norway (2023), styled an earthy-tone saree featuring an intricately crafted gold border with a minimalist blouse. Making a classic style statement in the contemporary Indian drape, Rani accessorised her Indian attire with a statement double-layered choker necklace and exquisite dangling earrings.

The highlight of Rani Mukerji's traditional yet timeless, alluring style was the minimal charm gold chain, which carried the alphabet initials of her daughter Adira's name. The personal touch in Rani's style resonates with the character of her movie, which won her the prestigious award.

Shehnaaz Gill

Drops New Track Khand Lagdi From Her Upcoming Film Ikk Kudi

Shehnaaz Gill has set social media ablaze with the release of her latest Punjabi song, Khand Lagdi, from her upcoming film Ikk Kudi. Released via her official Instagram handle, the track has already struck a chord with fans, who are loving her vibrant desi look and high-energy expressions.The song, which features vocals by Jasmine Sandlas, blends traditional Punjabi beats with a modern edge. Dressed in a printed suit paired with a bright pink dupatta, Shehnaaz channels full-on Punjabi festive flair, adding a visual charm to the already catchy track.

Sharing the song on Instagram, Shehnaaz wrote, "Khand Lagdi is out from the film Ikk Kudi, releasing on 31st October." The reel has quickly become a fan-favourite, with comments like "rocking anthem for weddings" and "Pretty ikk kudi" highlighting her enduring appeal. Many users have already begun using the track in their own reels, and it's expected to become a popular dance number this festive season.

About Khand Lagdi

The musical track by Jasmine Sandlas delivers a refreshing sound, with Sandlas's bold voice complementing Shehnaaz's screen presence perfectly. The song serves as the official promotional release from the upcoming film Ikk Kudi, setting a lively tone for what's to come.

Shehnaaz Gill's Career

Shehnaaz, who rose to fame through reality TV and has since made a successful transition into films and music, continues to win hearts with her authentic Punjabi style and relatable charisma. Khand Lagdi is yet another feather in her cap, showing her ability to shine in high-energy, culturally rich songs.

Film Release Postponed to 31 October

While the buzz around Khand Lagdi grows, the release of Ikk Kudi was postponed to 31 October 2025. The decision was taken in light of the severe flood situation in Punjab, as the makers chose to stand in solidarity with the affected communities. The team is also reportedly contributing to relief efforts, as confirmed by sources close to the production. With Khand Lagdi setting the stage, Ikk Kudi promises to be a festive entertainer with heart.